संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकाशन

RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050
Postal Reg.No.-13/Surguja DN/2023-2025

दैनिक घटती घटना

www.ghatatighatana.com
Ghatatighatana11@gmail.com

अम्बिकापुर,वर्ष 19,अंक -334 शनिवार ,07 अक्टूबर 2023 , पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

चुनावी घोषणाओं पर सुप्रीमकोर्ट सख्त

केंद्र सरकार,मुख्यमंत्रियों और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली,06 अक्टूबर 2023(ए)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा किये गये नकद सहायता वादों या वितरण को रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव घोषित करने की माँग की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की पीठ चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका की जांच करने पर सहमति व्यक्त की और केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और संबंधित दोनों राज्यों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

याचिकाकर्ता ने कहा, सरकार 'सार्वजनिक हित' में जो कुछ भी कहती है, उसका 'सार्वजनिक हित' में होना जरूरी नहीं है। सरकार को नकदी वितरित करने की अनुमति देने से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। चुनाव से छह महीने पहले ये चीजें शुरू हो जाती हैं। याचिका में कहा गया है कि अवैध मुफ्त वितरण के कारण बोझ अंततः करदाताओं पर पड़ता है।

पीठ ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा, 'चुनाव से पहले तमाम तरह के वादे किये जाते हैं और वह उन पर नियंत्रण नहीं रख सकती।'

हालाँकि, उसने आदेश दिया कि वह वर्तमान याचिका को अश्विनी कुमार उपाध्याय मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निपटाए जा रहे मुफ्त के मौजूदा मुद्दे के साथ टैग किया जायेगा।

पीठ ने मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यालय को प्रतिवादी के रूप में नामित करने के लिए याचिकाकर्ता से भी सवाल किया और उनकी जगह संबंधित राज्य सरकारों को रखने के लिए कहा।

याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्रीय बैंक को दोनों राज्यों को आगे ऋण देने से रोकने के लिए उन्होंने आरबीआई को भी प्रतिवादी पक्ष के रूप में शामिल किया। याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से अतार्किक मुफ्त वस्तुओं का वादा या वितरण आईपीसी की धारा 171-बी और धारा 171-सी के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के समान है।

याचिका में कहा गया है कि कथित तौर पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समेकित निधि के उपयोग के लिए चुनाव से पहले मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए।

अधिवक्ता उपाध्याय द्वारा दायर लंबित मामले में शीर्ष अदालत ने पहले टिप्पणी की थी कि राजनीतिक दलों द्वारा घोषित मुफ्त सुविधाएं राज्यों को आसन्न दिवालियापन की ओर धकेल सकती हैं और मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु मामले में माना था कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीतने के बाद द्रमुक द्वारा मुफ्त रंगीन टीवी सेटों के वितरण को भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता है।

राजनीतिक पार्टियों की मुफ्त रेवड़ी और धन बल पर रहेगी चुनाव आयोग की नजरःमुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार

मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित देश के कई राज्यों में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। इन राज्यों में अभी से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रमुख राजनीतक पार्टियों में चुनाव को लेकर घमासाम मचा हुआ हैऔर घोषणा पत्र जारी करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोकलुभावन घोषणा पत्र और धन बल का सहारा लेकर जनता के कीमती वोटों को खरीदने की कोशिश भी की जाती है इसके लिए बैंकों में अवैध रूप से लेनदेन के लिए रुपए ट्रांजेक्शन किए जाते है, ऐसे लोगों पर चुनाव आयोग शख्त कार्रवाई करेगी। सभी प्रदेशों में निष्पक्ष और शांतिपूवर्क चुनाव संपन्न कराने में चुनाव आयोग की भूमिका अहम रहती है। आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी तरह कमर कस ली है और जल्द ही छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में आचासंहिता लागू कर दी जाएगी। चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष पारदर्शी और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इन दिनों सीईसी की अगुआई में 17 सदस्यीय दल चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हैदराबाद में है। इस दौरान राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों और सरकार के अधिकारियों तथा प्रवर्तन एजेंसियों जेसे विभिन्न पक्षकारों के साथ बैठकें की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों को चुनाव के दौरान धन बल के इस्तेमाल करने के खिलाफ शख्त कार्रवाई करने का स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि प्रवर्तन एजेंसी एसी गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं करती तो हम करेंगे।

दिवाली के बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव

- » 15 दिसंबर से पहले नतीजे
- » छत्तीसगढ़ में दो चरण और अन्य चार राज्यों में
- » चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का तैयार किया प्लान

नई दिल्ली,06 अक्टूबर 2023(ए)। चुनाव आयोग ने इस साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने का संभावित प्लान तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में और राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक-एक चरण में मतदान हो सकता है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों का दौरा करने के बाद यह योजना तैयार की है। पांच राज्य नवंबर में दिवाली के बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक चुनाव कराने की योजना बना रहे हैं।इन सभी राज्यों में वोटों की गिनती 15 दिसंबर से पहले हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की मंजूरी के बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी। आज होने वाली निरीक्षकों की बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी की सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग-अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। चन्द्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना में सत्ता में है, जबकि भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुधरेगी बसों की सूरत

- » परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नए मानकों को दी मंजूरी

नई दिल्ली,06 अक्टूबर 2023(ए)। यात्री बसों को सड़क सुरक्षा की कसौटी पर पूरी तरह फिट बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत-एनसीएपी के तहत नए मानकों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। गडकरी ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किया कि बस बाडी के निर्माण के लिए अब नए मानक होंगे और ये ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चर्स (ओईएम) तथा बस बाडी बनाने वाली कंपनियों, दोनों पर समान रूप से लागू होंगे।

भारत में बसों की गुणवत्ता में आयेगा सुधार

गडकरी के मुताबिक बस दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह एक बड़ा कदम है, जो सड़क सुरक्षा के लिहाज से काफी कारगर साबित होगा। गडकरी ने अपनी पोस्ट मं कहा है कि बस निर्माण के नए मानकों को अपनाने के साथ देश में बसों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। ये इनमें सफर करने वाले लोगों को सुविधा और आराम का अहसास कराएंगी और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित करेंगी।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बसों की गुणवत्ता में होगा सुधार

गडकरी ने कहा कि नए मानकों का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति यानी दुर्घटना के समय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए मानकों के लिए मानक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इस पर लोगों के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। गडकरी ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष इस पहल का समर्थन करेंगे ताकि लोगों की सुरक्षा के सबसे अहम पहलू पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा सके।

गडकरी देश में बसों के स्तर पर पहले से सवाल खड़े करते रहे हैं। उन्होंने बस निर्माताओं और ओईएम से लगातार यह अपील की कि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बसों की गुणवत्ता में सुधार करें। उनका मानना है कि देश की आटो इंडस्ट्री में ओईएम के पास अपार अवसर हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत खराब है।

एनसीपी का असली हकदार कौन

अजित गुट की दलील पर क्या बोले शरद पवार के वकील?

नई दिल्ली,06 अक्टूबर 2023(ए)। एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस सुनवाई में अजित गुट के साथ-साथ शरद पवार खुद चुनाव आयोग पहुंचे। दोनों गुटों द्वारा पार्टी पर दावा ठोकने के बीच चुनाव आयोग में सुनवाई हो रही है।

एनसीपी पर अजित गुट का दावा

बता दें कि अजित पवार ने एनसीपी में बगावत करते हुए खुद का अलग गुट बना लिया है और पार्टी व चुनाव चिह्न पर दावा ठोक दिया है। इसी दावे के आधार पर वह चुनाव आयोग पहुंचे हैं। चुनाव आयोग में सुनवाई के दौरान शरद पवार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और अजित पवार की तरफ से वकील एन के कौल और मनिंदर सिंह उपस्थित हुए।

अजित गुट ने क्या दी दलील?

चुनाव आयोग के समक्ष अजित पवार गुट ने अपने समर्थन में दलीलें पेश कीं। अजित गुट ने कहा कि उन्हें एनसीपी में संगठन और विधायी विंग दोनों में समर्थन प्राप्त है। इसलिए चुनाव आयोग को अजित गुट को असली राजनीतिक पार्टी का दर्जा देना चाहिए।

क्या बोले वकील मनु सिंघवी?

वहीं, शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम आज पेश हुए हैं और दो घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली। उन्होंने कहा कि अजित पवार गुट द्वारा किए गए दावे बिल्कुल काल्पनिक है।

अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को

इस मामले में अब अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी। उम्मीद है कि सोमवार को भी अजित पवार गुट की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी।

अजित पवार का दावा है कि उन्हें महाराष्ट्र में 42 विधायकों, छह एमएलसी, नागालैंड में सभी सात विधायकों और लोकसभा व राज्यसभा में एक-एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। अजित पवार ने पार्टी और चिह्न दावा ठोकने के बाद 30 जून को चुनाव आयोग से संपर्क किया था।

2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन

- » 96 प्रतिशत से ज्यादा नोट बैंकों में वापस आए,
- » अभी 12 हजार करोड़ की करेंसी आना बाकी

नई दिल्ली,06 अक्टूबर 2023(ए)। 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोट से बदलने का 7 अक्टूबर आखिरी दिन है। इससे पहले आज यानी शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 96त्न से ज्यादा 2000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ गए हैं, जिनकी वैल्यू ₹3.43 लाख करोड़ है।इसमें से 87त्न नोट को बैंक में जमा किया गया है। बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है। इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन 30 सितंबर था, लेकिन आरबीआई ने आखिरी दिन इसकी मियाद 7 अक्टूबर 2023 कर दी थी।

7 अक्टूबर के बाद आरबीआई ऑफिस में बदल सकेंगे नोट

बैंक में नोट जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद 2000 रुपए के नोट आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में नोट बदले या जमा किए जा सकेंगे। एक बार में 20 हजार रुपए तक के 2000 के नोट बदले जा सकेंगे।

आपराधिक मामला दर्ज है इसलिए सरकार किसी व्यक्ति को सेवा से अयोग्य नहीं ठहरा सकती

कोच्चि ,06 अक्टूबर 2023(ए)। केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सरकार किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकती कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और शोबा अन्नम्मा ईपेन की खंडपीठ थी जिसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी आपराधिक मामले में बरी होने से कोई उम्मीदवार अपने-आप सेवा में शामिल होने का हकदार नहीं हो जाता है।अदालत ने कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि आपराधिक मामलों में जहां अभियोजन पक्ष के मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं, यदि सरकार अभियोजन के आरोपों और आपराधिक अदालत द्वारा व्यक्ति के चरित्र के बारे में

दर्ज किए गए निष्कर्ष सहित अन्य सामग्रियों के आधार पर एक राय नहीं बना सकती है, सरकार व्यक्ति के चरित्र की पृष्ठभूमि के बारे में अलग से जांच कराने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, केवल आपराधिक मामला दर्ज होने से सरकार ऐसे व्यक्ति को सेवा का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित नहीं कर सकती। हालाँकि केएटी ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन राज्य सरकार ने केएटी के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने याचिका पर गौर करते हुए कहा कि कांस्टेबल के खिलाफ दायर आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता (उसकी पत्नी) सहित सभी गवाह मुकर गए थे।अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष के आरोप को छोड़कर उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं थी। अकेले अभियोजन पक्ष के आरोपों के आधार पर चरित्र का आकलन करना सुरक्षित नहीं है।

7 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग

पांच महिलाओं समेत छह की मौत; 46 झुलसे

मुंबई ,06 अक्टूबर 2023(ए)।मुंबई में शुक्रवार तड़के एक 7 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। इस भीषण आग से पांच महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 46 झुलस गए। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।बीएमसी आपदा नियंत्रण की ओर से बताया गया कि शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे उपनगरीय गोरेगांव में 7 मंजिला जय भवानी बिल्डिंग की पार्किंग में लगी आग ने लग गई। आग में अब तक पांच महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। हादसे में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं, इनमें 18 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल हैं। इस दौरान 4 कार और 30 दोपहिया वाहन भी आग की चपेट में आ गए।

बीएमसी आपदा नियंत्रण ने कहा कि अग्निशमन कर्मियों के कड़े प्रयासों के बाद सुबह करीब 6.55 बजे आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है और जांच चल रही है।

सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर फिर बोला हमला

कोई सबूत नहीं,सभी आरोप झूठे

नई दिल्ली ,06 अक्टूबर 2023(ए)। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विपक्षी नेताओं के खिलाफ न केवल झूठे और मनगढ़ंत मामले दर्ज कर रही है, बल्कि उन्हें निशाना भी बना रही है।

उन्होंने आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी सरकार की आलोचना की और कहा कि शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि उनके पास रत्ती भर भी सबूत नहीं है और सब कुछ निराधार है।गाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा, उन्होंने हमारी इतनी जांच की, क्या कुछ पता चला? क्या आपने सुना कि

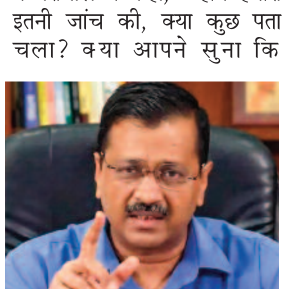

सुप्रीम कोर्ट ने कल (गुरुवार को) क्या कहा, पूरा शराब घोटाला झूठा है, एक पैसे का भी लेन-देन नहीं हुआ।उन्होंने कहा कि जज सबूत मांगते रहे लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, कुछ दिनों में शराब घोटाला बंद हो जाएगा और वे कुछ और लेकर आएंगे। वे सिर्फ लोगों को एजेंसियों और जांचों में उलझाए रखना चाहते हैं। वे न तो खुद काम करेंगे और न ही किसी को काम करने देंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर उनमें डर पैदा कर उन्हें बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ नेताओं को ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन को भी निशाना बनाया जा रहा है।

पत्रकारों के सवाल पर नीतीश के विधायक ने खोया आपा

धमकी देते हुए जमकर दी गालियां

पटना ,06 अक्टूबर 2023(ए)। बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल प्रमुख घटक दल जदयू के विधायक गोपाल मंडल को जब पत्रकारों का सवाल रास नहीं आया तो वे अपने असली रंग में आ गए और पत्रकारों को ही धमकी देते हुए जमकर गालियां दी। पूरा वाकया जदयू कार्यालय है। दरअसल, शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय में मौजूद थे और जदयू विधायक कार्यालय पहुंच गए। इसी क्रम में पत्रकारों ने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल से अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर जाने को लेकर सवाल पूछ डाले।जदयू के विधायक इन सवालों को लेकर अपनी सफाई दे रहे थे। इसे लेकर पत्रकारों ने उनसे जवाबी प्रश्न पूछ दिया, जो नीतीश कुमार के चहेते विधायक मंडल को

रास नहीं आया और वे पत्रकारों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि अरे यार, तू लोग पत्रकार हो, क्या हो, हमको मुश्किल लगता है।

इसके बाद जब पत्रकारों ने एक विधायक को रिवॉल्वर लेकर अस्पताल जाने को लेकर कई प्रश्न पूछे तो उन्होंने भड़कते हुए कहा कि हां लहराएंगे रिवॉल्वर। तू लोग मेरा बाप हो क्या, तुम सब मेरा बाप हो क्या? इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को जमकर गालियां दी।

बंगाल नगर पालिका नौकरी घोटाला

ईडी ने विभिन्न पदों के लिए तय रेट सूचियां हासिल की

कोलकाता ,06 अक्टूबर 2023(ए)। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगरपालिका भर्ती मामले के सिलसिले में 12 स्थानों पर दिन भर की मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने (ईडी) के अधिकारी शहरी नागरिक निकायों में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए दर सूची दर्शाते हुए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए। केंद्रीय एजेंसियों ने शुक्रवार को जिन 12 स्थानों पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया, उनमें राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष और उत्तर 24 परगना जिले की कई नगर पालिकाओं के कई अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के आवास शामिल थे।

सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों के अनुसार, मुख्य रूप से ग्रुप सी और ग्रुप डी ग्रेड में

फील्ड वर्कर, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, टाइपिस्ट और क्लर्क जैसे पदों की भर्तियों में अनियमितताएं की गईं, प्रत्येक के लिए अलग-अलग रेट लिस्ट थीं।

इन पदों का. छापेमारी करने वाले अधिकारियों द्वारा प्राप्त सुरागों के अनुसार टाइपिस्ट और ग्रुप सी क्लर्क के पदों के लिए सबसे अधिक दरें 6.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये के बीच थीं, इसके बाद ग्रुप डी क्लर्क के लिए 4.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच थी। सूत्रों ने कहा कि फील्ड कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और ड्राइवरों के लिए दरें सबसे कम 3.5 लाख रुपये से 4 लाख रुपये के बीच थीं।

इस बीच, राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष, जिनके आवास पर ईडी ने गुरुवार को लगभग 19 घंटे तक मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया, ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी का कदम जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के लिए है। मध्यमग्राम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के रूप में घोष की भूमिका ईडी की जांच के दायरे में है।

संपादकीय

अभियोजन का अनदेखा रूप

सवाल यह है कि वेबसाइट के प्रबंधकों ने कहां से पैसा लिया, उसकी जानकारी किसी सब-एडिटर या टेक्निकल कर्मचारी को कैसे हो सकती है? बात कर्मचारियों तक नहीं रही। बल्कि वेबसाइट पर लिखने वाले फ्रीलांसरों तक को नहीं बख्शा गया।
अगर किसी व्यक्ति और संस्था ने किसी प्रकार के गैर-कानूनी गतिविधि में भाग लिया हो, उसके खिलाफ न्याय की उचित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। यह बात वेबसाइट न्यूजक्लिक पर भी लागू होती है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहले से मुकदमा चल रहा था। पिछले अगस्त में उस पर एक नया मुकदमा अमेरिकी अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया, जिसमें आरोप है कि वेबसाइट को एक ऐसे अमेरिकी उद्योगपति ने धन दिया, जो चीन की तरफ से चलाए जाने वाले प्रचार अभियान को आगे बढ़ाता है। अखबारी रिपोर्ट साक्ष्य हो सकती है या नहीं, इस पर न्यायपालिका फैसला देगी। बहरहाल, इस आरोप की जांच में जो तरीका दिल्ली पुलिस ने अपनाया है, वह सचमुच अभूतपूर्व है। मंगलवार को न्यूजक्लिक से जुड़े दर्जनों स्थलों पर छापे मारे गए। हैरतअंगेज यह है कि इस दौरान उस वेबसाइट में करने वाले जूनियर स्तर के कर्मचारियों के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी और उनके मोबाइल फोन एवं लैपटॉप जब्त कर लिए।
सवाल यह है कि वेबसाइट के प्रबंधकों ने कहां से पैसा लिया, उसकी जानकारी किसी सब-एडिटर या टेक्निकल कर्मचारी को कैसे हो सकती है? बात कर्मचारियों तक नहीं रही। बल्कि वेबसाइट पर लिखने वाले फ्रीलांसरों तक को नहीं बख्शा गया। खुद दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उसने 46 व्यक्तियों से पूछताछ की और उनमें से कई को आगे भी इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। क्या यह न्याय की उचित प्रक्रिया है? या यह उसी सोच का एक और इजहार है, जिसमें आरोपी के साथ-साथ उसके परिजनों को भी दोषी मान कर दंडित किया जाता है? सामूहिक दंड आधुनिक न्याय सिद्धांत में सिरे से अस्वीकार्य है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह बिना किसी न्यायिक आदेश के विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध आरोपियों के घरों पर बुल्डोजर चलाए जा रहे हैं, उसी तरह न्यूजक्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। वैसे उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक यह है कि सभी कर्मचारियों को अभियुक्त मान लिया गया है। भारत के लिए यह अभूतपूर्व एवं अनदेखा तजुर्बा है।

महिला सशक्तिकरण और आरक्षण में फर्क है

संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों से पास होने के बाद महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है उस पर राष्ट्रपति के भी दस्तखत हो गए हैं यानी यह कानून बन गया है। जब से यह कानून संसद से पास हुआ तब से कोई दर्जन भर राजनीतिक रैलियों और सरकारी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए यह दावा किया है कि विपक्षी पार्टियां इतने बरसों से इसे पास नहीं करा पाई थीं लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध उनकी सरकार ने इसे कानून बनवाया है। अब महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि कानून कब लागू होगा, उसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। 2029 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2039 तक की समय सीमा का दावा किया जा रहा है। सरकार ने महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन के साथ जोड़ दिया है। सो, जब ये दोनों काम होंगे उसके बाद आरक्षण लागू होगा। आरक्षण लागू होने का समय कब आएगा इस बारे में पहले काफी कुछ लिखा जा चुका है।
अब सवाल है कि क्या महिला आरक्षण जब भी लागू होगा तब सिर्फ उसके दम पर महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? क्या इससे राजनीति में उनकी भूमिका ऐसी हो जाएगी कि वे अपने हिसाब से राजनीति को संचालित कर सकें? इन सवालों के जवाब बहुत मुश्किल नहीं है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू होने से लोकसभा और विधानसभाओं में महिला सांसदों व विधायकों की संख्या तो जरूर बढ़ जाएगी लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ जाएगी, यह नहीं कहा जा सकता है। संख्या में बढ़ोतरी इस बात की गारंटी नहीं है कि महिलाएं पार्टी के राजनीतिक मामलों में निर्णायक भूमिका निभाने लगेंगी या उनकी मर्जी के बगैर पार्टियों में फैसले नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो आज सभी पार्टियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नेता निर्णायक होते। आखिर दशकों से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी कुल 131 सीटें आरक्षित हैं। यह कुल संख्या का 24 फीसदी है। यानी लोकसभा में एक चौथाई सीटें एससी और एसटी के लिए

आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के इतने लोकसभा सांसद अलग अलग पार्टियों से जीत कर आते हैं। लेकिन क्या कोई यह दावा कर सकता है कि संसद में एससी और एसटी सांसद निर्णायक भूमिका निभाते हैं या अपनी पार्टियों में उनकी भूमिका इतनी अहम होती है कि उनके बगैर फैसला नहीं हो? यही स्थिति महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के बाद भी रहेगी। लोकसभा में महिला सांसदों की और राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन सिर्फ इतने भर से उनकी भूमिका नहीं बढ़ जाएगी, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हो जाएगा। आरक्षण से वे पार्टियों में महत्वपूर्ण हो जाएंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उनके सांसद या विधायक बनने से समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो दशकों से जारी आरक्षण की व्यवस्था से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का कल्याण हो चुका होता या स्थानीय निकायों में आरक्षण से महिलाएं ही राजनीतिक रूप से इतनी सशक्त हो गई होतीं कि उनको आगे की राजनीति के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं होती। लेकिन हकीकत यह है कि आजादी के बाद से अनुसूजित जाति व जनजाति के लोगों की शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति में बहुत कम अंतर आया है और उनकी राजनीतिक ताकत तो अब भी हाशिए पर है। यही स्थिति कमोबेश महिलाओं की भी है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टियां आरक्षण के कानून की मजबूरी में उनको टिकट तो देती हैं लेकिन उनको सशक्त बनाने के लिए काम नहीं करती हैं। उनको पार्टी के अंदर फैसला करने वाले अहम निकायों में जगह नहीं दी जाती है। उनकी राजनीतिक भूमिका नहीं बढ़ाई जाती है। उनको राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का काम नहीं किया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि बहुजन आंदोलन में अग्रणी रहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी अपनी पार्टी के अंदर न तो महिलाओं को आगे बढ़ा कर सशक्त किया और न अनुसूचित जाति के नेताओं को आगे बढ़ा कर उनको सशक्त बनाया। वे ऐसी भूमिका में थीं और उनके हाथ में इतनी ताकत थी कि वे एक साथ महिला और दलित दोनों का कल्याण कर सकती थीं। लेकिन इस देश की राजनीतिक व्यवस्था की जो मजबूरियां हैं उनकी वजह से वे भी बने बनाए ढर्रे पर चलती रहीं। हालांकि यह जरूर है कि पिछले 75 साल से भारत में चल रही लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक आदि वोट बैंक के रूप में उभरे हैं और चुनावों के समय पार्टियां इसी रूप में इनको एड्रेस करती हैं और उनका इस्तेमाल करती हैं।
इसलिए महिला आरक्षण अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि महिलाओं का राजनीतिक या सामाजिक रूप से सशक्तिकरण हो जाएगा। हां, यह जरूर है कि इससे एक आगाज होगा। लेकिन उस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का काम तो अंततः राजनीतिक दलों को ही करना होगा। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या कोई क्षेत्रीय पार्टी हो अगर पार्टियां महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उनको अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को निर्णायक भूमिका में लाना होगा और यह काम सिर्फ संख्या बढ़ाने से नहीं होगा। इसके लिए पार्टियों को अपने आंतरिक ढांचे में सुधार करना होगा। महिला काडर तैयार करना होगा। उनके राजनीतिक शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि राजनीतिक और विचारधारात्मक प्रशिक्षण के साथ महिलाएं स्वाभाविक रूप से आगे आएं। वे मुख्यधारा की राजनीति में अपनी जगह बनाएं और भूमिका निभाएं। यह तभी होगा, जब पार्टियों के शीर्ष पुरुष नेता उनको अपने से कमतर मानना बंद करेंगे। उनकी संख्या दिखाने या उन पर अहसान करने या उनका वंदन करने के लिए उनको आगे बढ़ाने की मानसिकता छोड़ेंगे। जब राजनीतिक व्यवस्था में उनको बराबरी की भूमिका मिलेगी और उनका आकलन भी उनकी योग्यता के आधार पर होगा तभी उनका सशक्तिकरण संभव है। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो गई या जयललिता, मायावती राबड़ी देवी, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनीं। इनमें एक ममता बनर्जी को छोड़ दें तो बाकी सब किसी न किसी बड़े राजनीतिक परिवार से थीं या किसी न किसी नेता ने उनको आगे बढ़ाया। यह भारत की नहीं पूरे दक्षिण एशिया की कहानी है। बहरहाल, महिला आरक्षण जरूरी है और इसका कानून बनना स्वागतयोग्य है। लेकिन यह नहीं माना जाना चाहिए कि इतने भर से महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा। उनका सशक्तिकरण तब होगा, जब स्वाभाविक रूप से राजनीति में उनके आगे बढ़ने की व्यवस्था बनेगी। पार्टियों के ढांचे में सुधार होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस नेता की सीट आरक्षण में आ गई उसके परिवार की महिलाओं को उस सीट से टिकट दे गई। इससे स्थानीय निकायों की तरह मुखिया पति या सरपंच पति वाली व्यवस्था लोकसभा व विधानसभाओं तक पहुंचेगी। कायदे से तो महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए था लेकिन देर से लागू होने में भी इसमें एक सिल्वर लाइनिंग यह देखी जा सकती है कि पार्टियां अगले कुछ बरसों का इस्तेमाल महिला काडर और महिला नेतृत्व तैयार करने के लिए करेंगी।

-अजीत द्विवेदी-

मणिपुर संकट में प्राचीन विवादों की प्रतिध्वनि मिलती

यह देखना निराशाजनक है कि मणिपुर लगातार अंधेरे में डूबता जा रहा है, लगभग पूरी तरह से प्रशासन के नियंत्रण से बाहर। भीड़ की हिंसा के शुरुआती उन्मादी सप्ताह के बाद, जो 3 मईको टोरबुंग गांव में विस्फोट हुआ और फिर सुनामी की तरह राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया, पैटर्न में शांति के संक्षिप्त दौर थे, जिससे शांति का वादा बेरहमी से टूट गया और समय-समय पर नए प्रकोप सामने आए। राज्य के किसी न किसी कोने में हिंसा और घोटाले का. यहां तक कि 19 जुलाई को सामने आए मैतेई भीड़ द्वारा दो कुकी महिलाओं को नग्न घुमाए जाने के 4 मई के वीडियो पर सार्वभौमिक आक्रोश ठंडा होना शुरू हो गया था, जब 6 जुलाई को अपहरण किए गए दो किशोरों की निर्मम हत्या की तस्वीरें सामने आई तो एक और आक्रोश भड़क उठा। तब से लापता - 25 सितंबर को सोशल मीडिया पर सामने आया।
बाद के मामले में हत्यारों की पहचान अब आधिकारिक है, हालांकि वे बहुत पहले से ज्ञात थे क्योंकि वे स्पष्ट रूप से सिम कार्ड बदलने के बाद मृत किशोरों के फोन का उपयोग कर रहे थे; इसलिए उनके आंदोलनों को डिजिटल रूप से पंजीकृत किया गया था। उनमें से चार को 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, और दो बच्चों को भी उठाया गया था, जो शायद गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक जोड़े के आश्रित थे। पहले के मामले में, सात पहचाने गए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उससे पहले, उनमें से कुछ को भीड़ के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इन दोनों संवेदनशील मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संभाला जा रहा है।

किशोरों की तस्वीरें सार्वजनिक होने के अगले दिन, वर्दी पहने स्कूल और कॉलेज के छात्र आक्रोश में इंफाल की सड़कों पर इकट्ठा हो गए। हर किसी को आश्चर्य और गुस्सा आया, जब दंगा नियंत्रण पुलिस ने बेवजह अत्यधिक हिंसा का जवाब दिया, न केवल आंसू गैस बल्कि पैलेट गन से रैलियों को तोड़ दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक सत्रह वर्षीय लड़के को उसके कंधों पर बिल्कुल सटाकर गोली मार दी गई, और उसका हाथ लगभग उड़ गया था; उसके शरीर में नब्बे से अधिक धातु के छर्रे लगे थे।
जैसे-जैसे संघर्ष खिंचता जाता है और गहराता जाता है, जैसा कि विद्वानों ने भविष्यवाणी की है, जो प्रदर्शित किया जा रहा है वह ईमानदार इतिहासकारों द्वारा भी किसी भी कड़वे संघर्ष के संपूर्ण सार को पकड़ने में कठिनाई है। ऐसा लगता है कि इतिहास लेखन कभी भी इस प्रश्न से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता÷ इतिहास किसका?÷ इसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण पर विचार करें जो कुकी-ज़ो जनजातियों और मेइतेईस के बीच चल रहे झगड़े से संबंधित है।
इस टकराव का एक कारण म्यांमार में सीमा पार से कुकी-गठबंधन चिन जनजातियों का कथित रूप से लगातार अवैध आप्रवासन और आरक्षित जंगलों में अतिक्रमण और पोस्ता की खेती के संबंधित मुद्दे हैं। कुकी गांवों की संख्या एक अजीब भूमि-धारण प्रथा के कारण बढ़ती जा रही है, जहां गांव का मुखिया सारी जमीन का मालिक होता है और ग्रामीण भूमिहीन किरायेदार होते हैं; इसलिए, उनमें से कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं और अपने गांव बसाते हैं। दरअसल, मौजूदा संकट के मद्देनजर, कुकी नेताओं ने मीडिया को दिए हाई-प्रोफाइल साक्षात्कारों में बार-बार इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि यह कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है और अपनी भूमि पर कहीं भी घूमना और बसना उनकी परंपरा है। यहां मुख्य शब्द भूमि है। आज हम जो संघर्ष देख रहे हैं, वह इस बात को लेकर है कि विभिन्न जनजातियाँ और समुदाय भूमि और उस पर कब्जे को कैसे देखते हैं। बिना किसी मूल्य निर्णय के, इस पर विचार करें÷ खानाबदोशों के लिए, जहां भी वे अपना तंबू लगाते हैं वह उनकी भूमि है, लेकिन बसे हुए कृषकों या सामंती रियासत और वास्तव में आधुनिक राज्य के लिए ऐसा नहीं है। जब ये सभी जनजातियाँ और समुदाय एक ही भौगोलिक क्षेत्र और युग में रहते हैं, तो संघर्ष की उम्मीद ही की जाती है। भूमि के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के बीच इस आवश्यक घर्षण को एंथनी सैटिन ने अपनी पुस्तक नोमैड्स÷ द वांडरर्स हू शेप्ड अवर वर्ल्ड में खूबसूरती से सामने लाया है। वह पौराणिक कथाओं में इस आशय के रूपक देखता है, जैसे कि मिस्र के सेठ और ओसिरिस, या होमर के ओडिसी के पात्र, लेकिन सबसे दिलचस्प बात बाइबिल में पहली हत्या है जहां एडम और ईव का पहला बेटा कैन, अपने छोटे को मारता है। भाई हाबिल. दिलचस्प बात यह है कि कैन मिट्टी जोतने वाला किसान है और हाबिल एक घुमंतू चरवाहा है। ये रूपक व्यावहारिक रूप से हर पुराने धर्म या संस्कृति में मौजूद हैं, जो मानव इतिहास में इस घर्षण की प्रारंभिक प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी सुनाने वाला कौन है - गतिहीन या भटकती हुई आबादी-दूसरा राक्षस या दानव होगा।

-त्रिवेणी-

वो कौन-से कारण हैं जिसके चलते देश में जाति आधारित गणना के पक्ष में नहीं है भाजपा?

देश में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडी के नेता अपनी रैलियों, सभाओं, संवाददाता सम्मेलनों और सोशल मीडिया पोस्टों के जरिये केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत गणना करवाये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कह चुके हैं कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है और सबसे बड़ी आबादी भी गरीब की ही है तथा उनकी सरकार अपनी हर नीति के केंद्र में इस वर्ग को रखती है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें। जहां तक जातिगत गणना के मुद्दे पर मोदी सरकार के आधिकारिक रुख की बात है तो वह अदालत में तभी स्पष्ट हो गया था जब सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि जनगणना करते समय अन्य पिछड़ी जातियों की गणना नहीं की जाएगी।
दरअसल उस समय तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह जनगणना में पिछड़ी जातियों की भी गणना करे। महाराष्ट्र की तत्कालीन शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का तर्क था कि 2011 की जनगणना में तत्कालीन सरकार ने एक आयाम जोड़ा था, जिसके अंतर्गत जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। सरकार ने वे आंकड़े उस वक्त जाहिर नहीं किए थे लेकिन उन्हें अब जारी किया जाना चाहिए। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के उस तर्क का विरोध करते हुए मोदी सरकार ने अदालत से कहा था कि उस समय इकट्ठे किए गए आंकड़े इतने अजीबो-गरीब थे कि उन्हें जाहिर करना उचित नहीं होगा।
जहां तक भाजपा के इस पर आधिकारिक रुख की बात है तो वह बहुत संभल कर चल रही है लेकिन विपक्ष का कहना है कि उसके दबाव के चलते एक दिन आयेगा जब भाजपा जाति आधारित जनगणना का समर्थन करेगी। वैसे यहां सवाल उठता है कि भाजपा आखिर क्यों नहीं चाहती कि जाति के आधार पर जनगणना हो? जबकि देखा जाये तो अन्य कारणों के अलावा, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा की प्रचंड जीत अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के मतदाताओं के बीच बनाई गई महत्वपूर्ण पैठ के कारण ही

संभव हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाजपा को अन्य जातियों या समुदायों से समर्थन नहीं मिला था। भाजपा अपने पारंपरिक समर्थकों, उच्च जातियों और उच्च वर्गों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के अलावा बड़ी संख्या में दलितों और आदिवासियों के मतों को जुटाने में भी कामयाब रही थी। इसलिए यह सवाल उठता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जाति-आधारित जनगणना कराने के बारे में अनिच्छुक क्यों लगती है?
जरा हालिया राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो बहुत कुछ समझ आ जायेगा। दरअसल 1990 के दशक की शुरुआत में वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था जिसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। इस फैसले ने भारत में चुनावी राजनीति की प्रकृति को बदल कर रख दिया था, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में इसका बड़ा असर हुआ था। मंडल के बाद की राजनीति के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और वह मजबूत होकर राज्यों में अपनी जड़ें जमाने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार इसके मजबूत उदाहरण हैं।
हम आपको बता दें कि 90 के दशक की शुरुआत में भाजपा को अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति के चलते ÷कमंडल राजनीति÷ के नाम से जाना जाता था। उस समय कमंडल को मंडल राजनीति का मुकाबला करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा था। भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तथा तमाम नेताओं के नेतृत्व में कड़ी मेहनत की और दो सांसदों वाली यह पार्टी केंद्र की सत्ता तक पहुँचने में तभी सफल रही जब उसे पिछड़ों और अति पिछड़ों का भरपूर समर्थन मिला। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव परिणाम इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।
उस समय भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन कर केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई और अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को किनारे रखकर एनडीए के साझा एजेंडे को आगे बढ़ाया। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि उस समय भले भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी लेकिन दोनों चुनावों में सर्वाधिक लाभ में क्षेत्रीय दल ही रहे थे। क्षेत्रीय दलों को 1998 में 35.5% और 1999 में 33.9% वोट मिले थे। यहां तक कि जब 2004 और 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने सरकार बनाई, तब भी क्षेत्रीय दलों को कुल मिलाकर 39.3% वोट मिले। क्षेत्रीय दलों को 2004 के लोकसभा चुनावों में 39.3% और 2009 के लोकसभा चुनावों में 37.3% वोट मिले थे। यहां तक कि जब भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान 31% वोटों के साथ बहुमत हासिल किया, तब भी क्षेत्रीय दलों ने कुल मिलाकर 39% वोट हासिल किए थे।
इसके अलावा, एक बड़ा आंकड़ा यह भी दर्शाता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा ने ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर अपनी पैठ बढ़ाई थी, जिससे क्षेत्रीय दलों के मूल समर्थन में ही सेंध लग गई थी जिससे उनका वोट शेयर घटकर 26.4% रह गया था। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि भाजपा ने पिछले एक दशक के दौरान ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर अपनी पैठ बढ़ाई है। आंकड़ों के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनावों में 22% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया, जबकि 42% ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया। लेकिन एक दशक के भीतर खासकर ओबीसी नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में उभार के बाद इस समुदाय का समर्थन भाजपा के साथ जुड़ गया जिससे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 44% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया, जबकि केवल 27% ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया था।
लेकिन ओबीसी वर्ग के भाजपा को प्रचंड समर्थन के बावजूद मामले में एक पेंच है। दरअसल लोकसभा चुनावों के दौरान तो ओबीसी मतदाताओं को भाजपा पसंद आती है लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की हो तो उनकी पसंद बदल भी जाती है। आंकड़ों के जरिये समझाने के लिए आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में केवल 11% ओबीसी ने राजद को वोट दिया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान 29% ओबीसी ने राजद को वोट दिया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में केवल 14% ओबीसी ने ही समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान 29% ओबीसी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था।
बहरहाल, जहां तक भाजपा की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना से बचने की बात है तो इसका एक प्रमुख कारण यह भी लगता है कि इस कवायद के चलते विभिन्न जातियों, विशेषकर ओबीसी जातियों के बारे में जो आंकड़े सामने आएंगे उससे क्षेत्रीय दलों को भाजपा पर दबाव बनाने के लिए नये मुद्दे मिल जाएंगे। यदि आंकड़े ऐसे आये कि केंद्र सरकार को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी कोटा को नया स्वरूप देना पड़ा तो इसके परिणामस्वरूप मंडल-2 जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इससे क्षेत्रीय दलों को नया जीवनदान मिल जायेगा। इसके अलावा कई दल ऐसे भी हैं जो भाजपा को राज्यों और केंद्र में चुनौती देने के लिए तमाम प्रयास करने के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं लेकिन यदि जातिगत आंकड़े सामने आ गये तो वह भाजपा को आसानी से घेर सकते हैं। भाजपा के पास इस समय ओबीसी के सबसे ज्यादा विधायक और सांसद भले हों लेकिन पार्टी कतई नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना करवा कर ऐसे मुद्दे को हवा दी जाये जिसको संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आज का भाजपा नेतृत्व 90 के दशक की मंडल-कमंडल राजनीति से भलीभांति वाकिफ भी है। वह जानता है कि अटल-आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या-क्या प्रयास करने पड़े थे और कैसे-कैसे दिन देखने पड़े थे इसलिए अब जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत का पालन करते हुए राजनीति की जा रही है।

-नीरज कुमार दुबे-

कह रहा हैं आईना

कह रहा हैं आईना इंसान से यही
जैसा हूं मैं तू भी तो बन जा वही
देखो वह सच देखो छलावा न करो
दामन में अपने सदा सच ही भरो
जो होता हैं उसीका अक्स दिखा दो
साफ तन ओ मन की तस्वीर बना दो
डरता नहीं कभी में बोलने से सच
तू भी नेक बन झूठ बोलने से बच
नाजुक मैं बड़ा टूट जाता जैसे दिल
दिल से दिल जोड़ देने वाला तू बन
देख मुझे चमक जातें हैं चेहरे सभी
तुझे देख कोई खुश हो ऐसा बन कभी
आईना हूं मैं सच बोलता हूं सदा
टूट कर भी झूठ न बोलूं ये रहा वादा
बिन टूटे बताता हूं तस्वीर एक ही
टूट कर बिखर जाते तो बताता मैं कई

जयश्री बिर्मी
अहमदाबाद, गुजरात

रौंद मुझे हंसने वाले

मेरे लबों कि मुस्कुराहट लगता अब
तो जैसे कहीं खो गई।
यूं लगे मुझको की मेरी कलम ही मेरे
दर्द की दवा हो गई।।
कितने हसीन ख्वाब संजोए थे मैंने
जिंदगी मे अपने कभी
टूटा हर एक ख्वाब मेरा, आज
मेरी जिंदगी तबाह हो गई।।
सोचा था कभी खुद को सोलह
श्रृंगार से हर पल सजाएंगे
ये सौलह श्रृंगार मेरे लिए बना
नहीं सोच अंखियां रो गई।।
अच्छा लगता था जब मेरी पायल
छेड़ती थी तेरे नाम लेके
आज मेरे नाम संग तेरा नाम जुड़ा
देख मुझे नफरत हो गई।।
मेरी ख्वाहिश,अंतर्मन को रौंद के
हंसने वाले मेरे क़ातिल
जीते-जी तू भी कभी तड़पेगा, वीना
आह दे तंहा सो गई।।

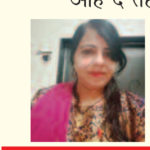

वीना आडवाणी तन्वी
नागपुर,महाराष्ट्र

सफलता का गीत

असफलता है एक चुनौती,
मत तुम हाथ मलो।।
चलो उठो एक नई राह पर
आगे बढ़े चलो।।
साहस लेकर,संग
आत्मबल बढ़ना ही होगा
जो भी बाधाएँ राहों में,लड़ना ही होगा
काँटे ही तो फूलों का
नित मोल बताते हैं
जो योद्धा हैं वे तूफ़ाँ से
नित भिड़ जाते हैं
मन में आशाओं को पालो,
क्योंकर कभी खलो।
चलो उठो एक नई राह पर
आगे बढ़े चलो।।
असफलता से मार्ग
सफलता का मिल जाता है
सब कुछ होना,इक
दिन हमको ख़ुद छल जाता है
असफलता से एक
नया,सूरज हरसाता है
रेगिस्तानों में मानव
तो नित नीर बहाता है
साधो करमों को ,गम से नही जलो।
चलो उठो एक नई राह पर चलो।।
भारी बोझ लिए देखो तुम,
चींटी बढ़ती जाती है
एक गिलहरी हो छोटी पर,
ज़िद पर अड़ती जाती है
हार मिलेगी,तभी
जीत की राहें मिल पाएँगी
और सफलता की
मोहक-सी बाँहें खिल पाएँगी
रहे दृढ़ सदा ही तुम टले से न टलो।
चलो उठो एक नई राह पर चलो।।

प्रो.(डॉ.) शरद नारायण खरे
मंडला मध्यप्रदेश

खोज

खोजता नहीं हूँ
तुमको इस विराट तत्व में
मिल जाते हो तुम
मुझे मेरे हृदय सत्ता में।
असीम अनंत ज्ञान है
नहीं कहीं बाहर
ढूंढने पर मिल जाता है
मन मस्तक की सत्ता में।
मिलता नहीं कभी
ध्यान और अनंत ज्ञान
जंगलों में भटकने से
वो तो मिल जाता है
मन की मौन सत्ता में।

राजीव डोगरा
जनयानकड़
कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

विधानसभा निर्वाचन 2023

सभी विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर अधिकारियों की बैठक के साथ प्रशिक्षण का भी हुआ आयोजन

» सेक्टर अधिकारियों के दायित्व, ईव्हीएम,वीवीपैट,बैलेट यूनिट, पोलिंग पार्टी व मतदान प्रक्रिया तथा अन्य विषयों के बारे में दी गई जानकारी

- संवाददाता -
अंबिकापुर,06 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर अधिकारियों की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला शुक्रवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सह कार्यशाला में तीनों विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर, अपर कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर लुण्ड्रा टी सी अग्रवाल, एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर अम्बिकापुर पूजा बंसल, तथा एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर सीतापुर रवि राही उपस्थित थे। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी लुण्ड्रा राम सिंह ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर नीरज कौशिक उपस्थित रहे।

विधानसभा निर्वाचन 2023 के मुख्य प्रशिक्षक डॉ. राजकमल मिश्रा व डॉ. एस. एन पांडेय ने प्रशिक्षण में सेक्टर अधिकारियों के दायित्व, ईव्हीएम, वीवीपैट, बैलेट यूनिट की जानकारी के साथ साथ पोलिंग पार्टी व पूरी मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सेक्टर अधिकारियों को सम्पत्ति विरूपण, आदर्श आचार संहिता, विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान दल रवानगी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्र के 100 मीटर क्षेत्र के प्रोटोकॉल, मतदान केंद्र भवन में लगने वाले पोस्टर आदि पर चर्चा कर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। विशेष रूप से सभी सेक्टर अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया।

इस दौरान बताया गया कि सभी सेक्टर अधिकारियों को निर्वाचन क्षेत्र का पूर्व भ्रमण करना होगा। साथ ही निर्वाचन दिवस पर अपने सेक्टर क्षेत्र में लगातार दौरा करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक दो-दो घण्टे में अपने रिटर्निंग अधिकारी व नियंत्रण कक्ष में जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही निर्वाचन के समय सभी सेक्टर अधिकारी को निविदत्त मतपत्र, मॉकपोल, एजेण्ट की नियुक्ति, डाक मतपत्र, निर्वाचन ड्यूटी सर्टिफिकेट, पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा भरना, वोटर पर्ची वितरण, मतदान प्रारंभ करने की प्रक्रिया, घोषणा पत्र जारी करने आदि के बारे में बताया गया। इस अवसर पर तहसीलदार नीतू भगत, अंकिता तिवारी, चन्द्रशिला, अंकिता पटेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी जेआर प्रधान, स्वीप सहायक नोडल अधिकारी गिरीश गुप्ता, डीएमसी समग्र शिक्षा रवि तिवारी,करन सिंह जोगी,जेराल्ड कुजुर, राजीव जयंत खानवलकर, संदीप पाण्डेय उपस्थित रहे।

पीजी कॉलेज ने चलाया नुक्कड़ नाटक द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान

- संवाददाता -
अंबिकापुर,06 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र-छात्राओं ने संस्था के प्राचार्य डॉक्टर रिजवान उल्ला के मार्गदर्शन में स्वीप सरगुजा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला प्रशासन के निर्देश पर गांधी स्टेडियम के सामने नुक्कड़ नाटक के द्वारा शत-प्रतिशत मतदान करने हेतु लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक के द्वारा बताया गया कि जिन युवक-युवतियों की आयु 18 वर्ष हो गई है और जिनका मतदाता सूची में नाम है। उन्हें निर्भीक स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। नाटक के द्वारा बुरे उम्मीदवार के जीतने पर क्या दुष्परिणाम होते हैं। किस प्रकार भ्रष्टाचार हो सकता है, किस प्रकार जन सामान्य को मिलने वाली शासकीय योजना में घोटाले हो सकते हैं प्रदर्शित किया गया ।

साथ ही नाटक में अच्छे उम्मीदवार की विशेषताओं को भी बताया गया ।शत प्रतिशत मतदान का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने नुक्कड़ नाटक देखा।इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी प्रोफ़ेसर शशिकला सनमानी एवं प्रोफेसर राजीव कुमार उपस्थित रहे ।साथ ही स्वयंसेवक गौतम गुप्ता, शिवम शर्मा,डॉली गुप्ता,रेनु खलखो,जानम खान, मान्या , मनसा, सोनम, प्रियंका, संगीता,करन सोनी, संतोषी ,विश्वजीत,करन मिर्धे,अभ्युदय,संजर,शिवम जायसवाल, सूरज,साहिल, विशाल ने सक्रिय रूप से सहभागिता की । इस कार्यक्रम में स्वीप सरगुजा की ओर से प्रीति तिवारी, इंदु मिश्रा ,कमलेश वर्मा, रजनीश मिश्रा, महिमा, किरण आदि उपस्थित थे।

संतान की दीर्घायु,आरोग्य और सुखमयी जीवन के लिए माताओं ने जिवित्पुत्रिका व्रत कर की पूजा-अर्चना

- संवाददाता -
अंबिकापुर,06 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमयी जीवन के लिए माताओं ने जिवित्पुत्रिका व्रत कर पूजा-अर्चना की। जिवित्पुत्रिका व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे ही जिला मुख्यालय अंबिकापुर में मंदिरों के अलावा व्रतियों ने अपने-अपने घरों में जितिया डाली स्थापित कर विधि विधान से पूजा-अर्चना किया। इस दौरान व्रति महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा। गुरूवार सप्तमी तिथि को नहाय खाय, शुक्रवार को अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास एवं शनिवार को नवमी तिथि को पारण होगा। व्रति महिलाओं ने बताया कि वह पुत्र की दीर्घायु के लिए जितिया का व्रत रखी है और संतान की दीर्घायु के लिए ईश्वर की आराधना कर रही है।

विभिन्न राजनीतिक दल को सौंपा गया बाल अधिकार घोषणा पत्र

- संवाददाता -
अंबिकापुर,06 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

यूनिसेफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार वेधशाला एवं प्रदेश की स्वैच्छिक संगठनों द्वारा बालसभा का आयोजन कर बाल घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बच्चों के इस घोषणा पत्र को प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा चुनाव लड़ने हेतु तैयार दावेदारों एवं प्रत्याशियों को सौंपा जा रहा है। इसका मकसद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राजनैतिक दलों द्वारा तैयार किए जाने वाले घोषणा पत्र में बाल घोषणा पत्र को शामिल कराना है।

यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के राज्य प्रमुख जाब जाकारिया, बाल परितोष दास सोशल पालिसी स्पेशलिस्ट के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ बाल अधिकार वेधशाला बच्चों के बीच से निकले मुद्दों को राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों एवं अध्यक्षों तक पहुंचा रहा है। इसी तारत य में छह

अक्टूबर को छत्तीसगढ़ बाल अधिकार वेधशाला के सरगुजा संभाग प्रभारी मंगल पांडेय एवं रणधीर सिंह सचिव प्रयास सोशल वेलफेयर सोसायटी ने विधायक प्रत्याशी भाजपा प्रबोध मिंज से मुलाकात कर उन्हें बच्चों का बाल घोषणा पत्र सौंपा। और इसे भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया। स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बच्चों के बीच से निकले मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि बच्चों की मांग है कि छात्र चाहे जिस जाति-धर्म का हो, गरीब, मध्यम चाहे अमीर परिवार का हो, सभी को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। इन्हें किताब के साथ कॉपी भी दिया जाए। यूनिफार्म के साथ अन्य जरूरी सामग्री जूता, स्वेटर आदि उपलब्ध कराया जाए। गांवों में खेलकूद हेतु समुचित व्यवस्था की मांग बच्चों द्वारा बालसभा के दौरान की गई। विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों की उपलब्धता एवं गुणवत्तायुक्त विद्यालय हर गांव में खोलने का मुद्दा बच्चों ने उठाया।

नागपुर-उदलकछार स्टेशन पर रुकेगी अंबिकापुर-दुर्ग व अंबिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस

- संवाददाता -
अंबिकापुर,06 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

दुर्ग एक्सप्रेस 18241/18242 तथा अंबिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस 18756/18755 ट्रेन अब कुछ दिनों के बाद नागपुर एवं उदलकछार स्टेशन पर रुकेगी। इसका एप्रूवल रेलवे बोर्ड ने दे दिया है। बीते दिवस रेलवे संबंधी सरगुजा संसदीय क्षेत्र की मांगों के संदर्भ में केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने रेल मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों ट्रेनों यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज कोरिया-मनेंद्रगढ़ जिला अंतर्गत आने वाले स्टेशन नागपुर एवं उदलकछार में करने हेतु रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सार्थक चर्चा की। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित को रेल मंत्री ने दिशा-निर्देश जारी किया। परिणामस्वरूप दोनों स्टेशनों पर अंबिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस व अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित हो गया है। इसका आदेश भी रेलवे बोर्ड ने तुरंत पारित कर दिया। ज्ञात हो कोरोना के बाद प्रारंभ हुई रेल गाडियों का स्टॉपेज छोटे स्टेशनों से बंद कर दिया गया था। इससे कोरिया तथा मनेंद्रगढ़ जिले के लोग ट्रेन की सुविधा से महरूम हो गए थे। फिर से उन्हें यह सौगात केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के प्रयास से मिली है। इसके साथ ही उन्होंने अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन ट्रेन को दो दिवस चलाने तथा ट्रेन ऑन डिमांड को समाप्त करने, कोरोना के समय से जो स्टॉपेज बंद किए गए हैं उन्हें प्रारंभ करने, अंबिकापुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने, ऊर्जा कॉरिडोर से संबंधित सभी कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने, बरवाडीह-रेणुकूट रेल मार्ग के संबंध में स्मरण कराया। सभी बिंदुओं पर रेल मंत्री ने यथाशीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

हाथ-मुक्का व डंडे से पीटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट,आरोपी पति गिरफ्तार

- संवाददाता -
अंबिकापुर,06 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम चिरगा नवापारा में 4 अक्टूबर की रात को आपसी विवाद में पति ने पत्नी को हाथ-मुक्का व डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार करमी उर्फ गुड्डी पति विजय सोनवानी उम्र 40 वर्ष लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम चिरगा नावापारा की रहने वाली थी। 4 अक्टूबर की रात को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया था। गुस्से में आकर विजय ने हाथ-मुक्का व डंडे से पत्नी करमी की बेदम पिटाई कर दी। इससे महिला की मौत मौके पर ही हो गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद पति मौके से फरार हो गया। 5 अक्टूबर की सुबह पड़ोसी

पीतांबर ने घटना की जानकारी लुण्ड्रा थाने को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी लुण्ड्रा उप निरीक्षक सम्पत राम पोटाई, सहायक उप निरीक्षक राकेश मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक नामूल राम, महिला आरक्षक प्रेमा मरावी, अनिल बड़ा, टेबिल सिंह, जागेश्वर तिर्की, निरंजन बड़ा, अनिल मरावी शामिल रहे।

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित

- संवाददाता -
अंबिकापुर,06 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया है कि एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना ÷मिशन शक्ति÷ की शुरूआत की गई है। मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले मे 08 स्वीकृत संविदा पदों की पूर्ति हेतु आवेदन 25 अक्टूबर 2023 कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। संबंधित विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाईट ॑ऐनतहनरंण्हवअण्पद व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

दशहरा महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर समिति की हुई बैठक

- संवाददाता -
अंबिकापुर,06 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

दशहरा महोत्सव हेतु सरगुजा सेवा समिति व नागरिक समिति की संयुक्त बैठक पीजी कॉलेज मैदान में हुई। बैठक में दशहरा महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों की गति देने के संदर्भ में चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि रावण के पुतला हेतु ढांचा तैयार है, वहीं मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले का ढांचा शेष है। बाकी अंतिम रूप ढांचा तैयार होने के बाद दिया जाएगा। महोत्सव के दौरान होने वाले रामचरित्र मानस, शैला नृत्य व अन्य कार्यक्रमों हेतु प्रभारी बनाए गए। इनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न होंगे। मंच व्यवस्था व अन्य जरूरी विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सरगुजा सेवा समिति की अध्यक्ष रजनी रविशंकर त्रिपाठी, नागरिक समिति के अध्यक्ष अजय अग्रवाल, आलोक दुबे, कृष्ण कुमार अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, संजय अग्रवाल, करता राम गुप्ता, संजय मित्तल, प्रवीण गुप्ता, विद्यानंद मिश्रा, सूर्य प्रकाश साहू, महेंद्र अग्रवाल, प्रयागराज साहू, शुभम अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, नीरज पांडेय, मधुसूदन प्रसाद शुक्ला, तपन अग्रवाल, आयुष पांडेय, दीपक ठाकुर, सुशील गोयल, शुभम गोयल, अनिल जायसवाल, आशीष मंगल, चंद्र प्रताप सिंह, वेदांत तिवारी, बजरंग जिंदल, शेखर सोनी, विक्की समद्दार, सर्वेश तिवारी, देवकी त्रिपाठी, किरण सोनी, राजन सोनी, ऋषभ गर्ग, दिव्यांश केसरी, मधु चौदहा, प्रियंका चौबे, संगीता सोनी, मंजूषा भगत, बबली नेताम, पूजा सोनी, पूनम सिंह, नीलम राजवाड़े, आकाश मंडल, राजेश राय सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ध्वनि प्रदूषण को लेकर परिवहन व यातायात विभाग नें की संयुक्त कार्यवाही

- संवाददाता -
सूरजपुर,06 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

टोल नाका के पास संयुक्त रूप से परिवहन विभाग और यातायात विभाग द्वारा भारी वाहन में लगे प्रेशर हॉर्न की जाँच की गई। जाँच में 17 वाहनो में प्रेशर हॉर्न लगा हुआ पाया गया। जिसमें कुल 22000 हजार का चालान केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के उल्लंघन में किया गया और प्रेशर हॉर्न को निकाल कर जप्त किया गया।

किसानों की सहूलियत के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में खुलेंगे 25 नवीन धान उपार्जन केंद्र,खाद्य विभाग से आदेश जारी

» सरगुजा में बतौली विकासखण्ड के बोदा व मंगारी और सीतापुर के बेलजोरा में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले जाने की अनुमति, अब जिले में कुल 50 उपार्जन केंद्र

- संवाददाता -
अंबिकापुर,06 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों-ग्रामीणों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षो के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इस आशय का आदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके तहत नवीन धान उपार्जन केंद्रों में सरगुजा (अम्बिकापुर) जिले के बतौली विकासखण्ड के बोदा व मंगारी तथा सीतापुर विकासखण्ड के बेलजोरा में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। गौरतलब है कि सरगुजा जिले में विगत वर्ष तक 47 उपार्जन केंद्र थे, इस वर्ष 03 नवीन उपार्जन केंद्र स्वीकृत हुए हैं जिससे अब सरगुजा जिले में कुल 50 उपार्जन केंद्र होंगे।

इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है जिनमें राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखण्ड के अंतर्गत देवकट्टा और डोंगरगांव विकासखण्ड के संबलपुर, सक्ती जिले के सक्ती विकासखड के अंतर्गत नन्दौरखुर्द, महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखण्ड के अंतर्गत बोडराबांधा और आमगांव, मुंगेली जिले के लोरमी विकासखण्ड के औराबांधा, बलरामपुर जिले के रामचन्द्रपुर विकासखण्ड के डुमनपान, कोण्डागांव जिले के फरसगांव विकासखण्ड के बड़ेओड़गांव, केशकाल विकासखण्ड के कुएमारी और कोण्डागांव विकासखण्ड के नवागांव तथा गरियाबंद जिले के छुरा विकासखण्ड के पीपरछेड़ी और उत्तर बस्तर कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखण्ड के बंडापाल व कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के बेलगाल में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे।

भारत से तनाव के बीच आठ सिख युवाओं की गिरफ्तारी, घातक हथियार और गोला-बारूद रखने के आरोप

टोरंटो,06 अक्टूबर 2023 । कनाडा की पुलिस ने ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन शहर में आठ सिख युवाओं को गिरफ्तार किया है। इन युवाओं पर गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त होने का आरोप है। लोडेड या प्रतिबंधित बंदूक जैसे हथियार या आग्नेयास्त्र रखने के संबंध में 19 से 26 साल की उम्र के आठ युवाओं पर मामला दर्ज किया गया है।

गोलीबारी की खबर के बाद आठ की गिरफ्तारी

पील रीजनल पुलिस के मुताबिक, 2 अक्टूबर की रात को ब्रैम्पटन के डोनाल्ड स्टीवर्ट रोड और ब्रिस्डेल ड्राइव इलाके में गोलीबारी की सूचना मिली। टैक्टिकल यूनिट की सहायता से पुलिस ने आठ व्यक्तियों को घरों से निकाला गया और गिरफ्तार किया गया। गोलीबारी के बारे में एक सवाल पर पुलिस ने पुष्टि की है कि किसी को चोट नहीं आई है।

9 एमएम की बेरेटा बंदूक जब्त की गई

8 सिख युवाओं की गिरफ्तारी भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच हुई है। 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हैं। गिरफ्तारी के एक दिन बाद, आपराधिक जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने वारंट के आधार पर 9 मिमी बेरेटा बन्दूक जब्त की।

पुलिस ने बताई आठों सिख युवाओं की पहचान

जिन लोगों पर ÷भरी हुई अवैध या प्रतिबंधित बंदूक÷ रखने का आरोप है, पुलिस ने उनकी पहचान भी सार्वजनिक की है। इन लोगों में ब्रैम्पटन में रहने वाले जगदीप सिंह (22), एकमजोत रंधावा (19), मनजिंदर सिंह (26), हरप्रीत सिंह (23), रिपनजोत सिंह (22), जापानदीप सिंह (22), लवप्रीत सिंह (26) शामिल हैं।

गोला-बारूद का लापरवाही से भंडारण

एक अन्य आरोपी- 21 वर्षीय राजनप्रीत सिंह पर लोडेड, अवैध या प्रतिबंधित बंदूक रखने के अलावा आग्नेयास्त्र, हथियार, प्रतिबंधित उपकरण या गोला-बारूद के लापरवाही से भंडारण का आरोप भी लगाया गया है। जमानत की सुनवाई के लिए आठों आरोपियों को ब्रैम्पटन में ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया गया था।

कनाडा और भारत के तनाव का कारण

गौरतलब है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की ÷संभावित÷ संलिप्तता के आरोप खुद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगाए हैं। इन आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत कनाडा के आरोपों को ÷बेतुका÷ और ÷प्रेरित÷ बताते हुए दृढ़ता से खारिज कर चुका है। भारत ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों और भारत के राजनयिक परिसरों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई है।

दूसरे देशों पर नियम थोपना रुकना चाहिए : पुतिन

सोची ,06 अक्टूबर 2023। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि किसी अन्य देश पर नियम थोपना प्रतिबंधित होना चाहिए और किसी को भी दूसरों के लिए दुनिया पर शासन करने का अधिकार नहीं है।

सोची में वल्दाई डिस्कशन क्लब के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए पुतिन ने एक खुली, परस्पर जुड़ी और विविधतापूर्ण दुनिया बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां अन्य देशों पर नियम थोपना प्रतिबंधित होना चाहिए।

उन्होंने कहा, किसी भी देश या लोगों पर यह थोपना वर्जित होना चाहिए कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए। केवल सच्ची सांस्कृतिक और सभ्यतागत विविधता ही लोगों की भलाई और हितों का संतुलन सुनिश्चित करेगी।

पुतिन ने कहा, कोई भी हर किसी के लिए फैसला नहीं करेगा, और हर कोई हर चीज पर फैसला नहीं करेगा, लेकिन जो लोग किसी विशेष समस्या से सीधे प्रभावित हैं, वे इस बात पर सहमत होंगे कि क्या करना है और कैसे करना है।

रूसी राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक सभी देशों की राय का सम्मान नहीं किया जाता और सभी सुरक्षित महसूस नहीं करते तब तक स्थायी वैश्विक शांति स्थापित नहीं होगी।

भारत-अमेरिकी सैन्य स्नाइपर्स का संयुक्त प्रशिक्षण,भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने किया अलास्का का दौरा

अलास्का,06अक्टूबर 2023 । भारतीय और अमेरिकी सैन्य स्नाइपर्स ने युद्ध अभ्यास को बंद करने से पहले अलास्का में संयुक्त प्रशिक्षण किया। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने अभ्यास के समापन समारोह के लिए अलास्का का दौरा किया। उन्होंने अलास्का में युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के सैनिकों की गतिविधियों की सराहना की है। भारतीय राजदूत ने अमेरिकी सेना और 11वें एयरबोर्न डिवीजन की मेजबानी के लिए धन्यवाद भी किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए तरनजीत सिंह संधू ने कहा, रक्षा साझेदारी को और गहरा करते हुए। भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों को एकसाथ अभ्यास करते हुए देखने का अनुभव अच्छा था। अमेरिकी सेना और 11वें एयरबोर्न डिवीजन को धन्यवाद।

भारतीय-अमेरिकी सैन्य स्नाइपर्स का संयुक्त प्रशिक्षण पिछले हफ्ते भारतीय और अमेरिकी सेना ने चल रहे युद्ध अभ्यास के साथ अलास्का सामरिक अभ्यास भी किया। इस अभ्यास ने दोनों सेनाओं के बीच के संबंधों को मजबूत किया है। युद्ध अभ्यास के 19वें संस्करण की शुरुआत 25 सितंबर को हुई थी, जो कि आठ अक्तूबर तक चलेगी। यह एक वार्षिक अभ्यास है जो भारतीय और अमेरिकी सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इससे पहले इस अभ्यास का आयोजन नवंबर 2022, उत्तराखंड के औली में किया गया था।

अभ्यास के इस संस्करण में 350 कर्मियों वाली भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने भाग लिया है, जिसमें मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट भी शामिल है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सेनाओं ने शून्य से नीचे आर्कटिक परिस्थितियों में उच्चकोण बचाव और निकासी अभ्यास का अभ्यास किया गया।

नवाज शरीफ के देश लौटने में देरी,पार्टी के शीर्ष नेता बोले-अभी समय सही नहीं

इस्लामाबाद,06 अक्टूबर 2023। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के देश लौटने की तमाम अटकलों को उनकी पार्टी ने खारिज कर दिया है। खबरों के मुताबिक पार्टी के शीर्ष नेताओं के समूह ने नवाज शरीफ को सलाह दी कि वह अभी देश न ही लौटे। सूत्रों के मुताबिक उन्हें कहा गया कि अभी सही समय नहीं है। गौरतलब है कि नवाज शरीफ ने 21 अक्तूबर को लंदन में आत्म निर्वासन से लौटने की योजना बनाई थी।

जनवरी में होने वाले आम चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) का नेतृत्व करने की नवाज शरीफ की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी समूह का मानना है कि लोग बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते बिजली के बिलों से परेशान है। पीएमएल-एन सुप्रीमो के देश लौटने को लेकर लोगों में खासा दिलचस्पी नहीं है।

पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो उन्हें राय दी गई कि तारीखों की घोषणा के बाद वे देश लौट आएं। अभी आम चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पिछले महीने घोषणा की थी कि आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे।

हालांकि वापस न लौटने की खबरों के बीच पीएमएल-एन के एक समूह ने कहा कि अगर नवाज शरीफ देश वापस नहीं लौटते हैं तो पार्टी के खिलाफ जनता में नकारात्मक प्रभाव जाएगा। उन्हें देश लौटने के अपने फैसले में कायम रहना चाहिए। वहीं पीएमएल-एन के सीनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को देश वापसी होना तय है और कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पीएमएल-एन के सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने पार्टी सुप्रीमो द्वारा देश में अपनी वापसी टालने की अफवाहों का खंडन किया है।

नवाज शरीफ कहां हैं ?

लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा चार सप्ताह के लिए जमानत दिए जाने के बाद नवाज शरीफ ने नवंबर 2019 में चिकित्सा आधार पर देश छोड़ दिया। वह कोट लखपत जेल लाहौर में अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की सजा काट रहे थे।

अमेरिका में भारतीय मूल के दंपती और दो बच्चों के शव बरामद,न्यूजर्सी में खरीदा था 5.28 करोड़ का मकान

न्यूयॉर्क,06 अक्टूबर 2023 । अपराध की दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय मूल के पति-पत्नी और उनके दो नाबालिग बच्चों को अपने ही घर में मृत पाया गया है। न्यू जर्सी पुलिस इस मामले को हत्याकांड मानकर जांच कर रही है। प्लेन्सबोरो पुलिस विभाग ने कहा, मृतकों की पहचान 43 वर्षीय तेज प्रताप सिंह, पत्नी सोनल परिहार (42) के रूप में हुई है। दंपती के 10 और 6 साल के बच्चों को भी मृत पाया गया। पुलिस के मुताबिक चारों शव अमेरिकी समय के अनुसार, बुधवार शाम 4:30 बजे के आसपास बरामद किए गए।

आम जनता को बड़ा खतरा नहीं

क्राइम के बारे में मिडलसेक्स काउंटी के अभियोजक योलान्डा सिस्कोन और प्लेन्सबोरो पुलिस विभाग के प्रमुख इमोन ब्लैंचर्ड ने बताया, पुलिस हत्या के एंगल से मौत के कारणों की जांच कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, 4 अक्टूबर की शाम अधिकारियों के पास प्लेन्सबोरो में 911 कॉल आई। जांच करने पहुंची पुलिस को घर के भीतर से चार शव बरामद हुए। शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चला है कि आम जनता को कोई बड़ा खतरा नहीं है।

सामुदायिक रूप से सक्रिय थे पति-पत्नी

पुलिस ने इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी देने के लिए प्लेन्सबोरो पुलिस विभाग से संपर्क करने की अपील भी की है। रिपोर्ट के अनुसार परिवार में किसी अनहोनी का पता उस समय चला जब एक रिश्तेदार ने फोन किया। रिश्तेदारों के हवाले से सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट में बताया गया कि चारों की मौत की खबर झटका देने वाली है, क्योंकि भारतीय मूल का यह दंपती बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। विशेष रूप से तेज प्रताप सिंह समुदायिक काम में सक्रिय रहते थे।

5.28 करोड़ में खरीदा घर, पड़ोसी ने बताया व्यवहार

न्यूज 12 न्यू जर्सी की रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों में से एक विकॉफ और एक मिलस्टोन रिवर स्कूल में पढ़ाई करते थे। खबरों के अनुसार, तेज सिंह और सोनल परिहार ने अगस्त 2018 में 6.35 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 5.28 करोड़ रुपये) में अपना घर खरीदा था। पड़ोसियों ने भी परिवार को मिलनसार बताया। गोपनीयता की शर्त पर एक महिला ने बताया, उसकी बेटी आमतौर पर स्कूल जाते समय बस स्टॉप पर 6 साल की लड़की से मिलती थी, लेकिन उस लड़की का दिखाई नहीं देना अटपटा लगा। महिला के मुताबिक उसने उस सुबह परिहार को मैसेज भी भेजा लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

दंपती इंजीनियर और एचआर प्रोफेशनल

मौत के बाद आई मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अनुसार तेज नेस डिजिटल इंजीनियरिंग के लिए लीड एपीआईएक्स इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। रिश्तेदारों के मुताबिक तेज आईटी, जबकि पत्नी सोनल परिहार एचआर प्रोफेशनल थीं।

17 लाख अप्रवासी अवैध,सख्ती के खिलाफ कराची में प्रदर्शन

कराची,06 अक्टूबर 2023। पाकिस्तान में बिना दस्तावेज वाले हजारों अप्रवासियों पर निर्वासन की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान सरकार की सख्त कार्रवाई से भड़के अफगानी लोगों ने क्वेटा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। देश में उग्रवाद और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रही पाकिस्तान सरकार के इस एक्शन से अफगान नागरिकों सहित हजारों ऐसे अप्रवासियों को देश से निकाले जाने का खतरा है जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है।

देश छोड़ने या कारावास और निर्वासन का जोखिम

क्वेटा में यूएनएचसीआर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे गायक बैनर लेकर पहुंचे थे। नारेबाजी करते दर्जनों अफगान गायक पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसमें बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को देश छोड़ने या कारावास और निर्वासन का जोखिम उठाने की चेतावनी दी गई है।

तालिबान शासन के उत्पीड़न की आशंका

समय सीमा निर्धारित करने के पाक सरकार के फैसले से अफगान नागरिकों सहित हजारों अप्रवासियों पर असर होगा, जिनके पास 1 नवंबर की समय सीमा से पहले पाकिस्तान में रहने के लिए जरूरी कानूनी दस्तावेज नहीं होंगे। प्रदर्शनकारी अफगान गायकों का कहना है कि वे अफगानिस्तान नहीं लौटना चाहते। तालिबान शासन के उत्पीड़न की आशंका से घिरे गायकों का सवाल है कि अगर उन्हें अफगानिस्तान लौटने पर मजबूर किया गया तो उनका भविष्य क्या होगा।

गायकों को बुरा मानते हैं अफगानिस्तान के तालिबानी शासक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक अफगान गायक अहमद शदायी ने कहा, भले ही हमारे पास वैध शरणार्थी होने का प्रमाण है, इसके बावजूद उन्हें निर्वासन का डर सता रहा है। उन्हें अपने और परिजनों के भविष्य की चिंता सता रही है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि तालिबान गायकों को बुरा मानते हैं। ऐसे में वे अफगानिस्तान में सुरक्षित नहीं होंगे। क्वेटा पहुंचे प्रदर्शनकारी अपने साथ गायन और वाद्ययंत्र भी लाए थे।

2021 में छोड़ा अफगानिस्तान, अब पाकिस्तान में भी संकट

गौरतलब है कि तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्ज़ा किया था। तालिबानी शासन आने के बाद काबुल छोड़कर भागे शेडेयी भी विरोध-प्रदर्शन में शामिल थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पहले अफगानिस्तान से जान बचाकर भागे, अब पाकिस्तान में भी उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है।

कानूनी दस्तावेजों की कमी के कारण 1700 गिरफ्तार

मानवाधिकार के इस मुद्दे पर यूएनएचसीआर क्वेटा के प्रवक्ता हुमेरा करीम ने कहा कि वे गायकों की मदद करने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिकारियों ने गुरुवार को कराची में अवैध अफगान शरणार्थियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। 1700 लोगों को कानूनी दस्तावेजों की कमी के कारण गिरफ्तार किया गया।

पाकिस्तान अतिथि सत्कार से थक चुका है

कार्यवाहक गृह एवं कारागार मंत्री, ब्रिगेडियर. (सेवानिवृत्त) हारिस नवाज ने कहा कि अवैध शरणार्थी पाकिस्तान की स्थानीय आबादी के बीच रह रहे हैं। नरमी नहीं बरते जाने का साफ संदेश देते हुए नवाज ने कहा, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति का संकेत दिया और कहा पाकिस्तान अब हम अपने आतिथ्य सत्कार से बहुत ज्यादा थक चुका है।

अमेरिकी सेना के हथियार अफगान लोगों के पास

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शरणार्थी आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल पाए गए हैं। नवाज के अनुसार, हम वास्तविक दोषियों की पहचान करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। सभी अवैध अप्रवासियों को घर वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने 2021 में अफगानिस्तान छोड़ा। उन्होंने अफगानिस्तान में कई हथियार छोड़े जो अब आतंकवादी संगठनों के पास हैं।

बलूचिस्तान और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी हमले

मंगलवार को पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्री सरफराज बुगती ने निर्वासन के लिए एक नवंबर की समय सीमा का एलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार का फैसला बलूचिस्तान और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी हमलों की लहर के बाद आया है।

14 हमलों में अफगान नागरिकों का हाथ,पाक के पास सबूत

बुगती ने कहा, ÷जनवरी से अब तक 24 आत्मघाती हमले हुए हैं; इन 24 में से 14 हमलों में अफगान नागरिकों का हाथ रहा है।÷ उन्होंने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के भीतर से हमला किया गया है और अफगान नागरिक इनमें शामिल हैं। पाक सरकार के पास पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर के बाद अवैध नागरिकों को निर्वासित किया जाएगा। साथ ही उनकी संपत्ति और कारोबार भी जब्त किए जाएंगे।

निर्वासन के खतरे पर क्या बोले अफगान सरकार के मंत्री

पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई के बीच अफगान सरकार के मंत्री ने एक्शन को अनैतिक करार दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से नियुक्त कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने 31 अक्टूबर तक अफगान शरणार्थियों को निष्कासित करने के फैसले की कड़ी निंदा की।

तुर्की के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में हवाई हमले किए

दमिश्क,06 अक्टूबर 2023 । तुर्की के ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने उत्तरी और पूर्वी सीरिया में कुर्द मिलिशिया के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। हमलों में 24 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। हमले में कुर्द लड़ाकों में से 15 हताहत हो गए।

मानवाधिकारों के लिए सीरियाई वेधशाला ने कहा कि तुर्की वायु सेना ने कुर्द स्थलों पर तीन लड़ाकू विमानों और 21 ड्रोन द्वारा 24 हवाई हमले किए। हमलों में तेल, बिजली और जल स्टेशनों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिससे काफी नुकसान हुआ।

तुर्की की गोलाबारी के कारण उत्तरपूर्वी प्रांत अल-हसाका में दो बिजली संयंत्र और एक जल स्टेशन सेवा से बाहर हो गए। हमलों में वृद्धि तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान द्वारा जारी की गई धमकियों के बाद हुई

है। उन्होंने तुर्की की राजधानी अंकारा में एक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सीरिया और इराक में विस्तारित सीमा पार अभियान की चेतावनी दी थी, जिसमें दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे।

परमाणु संयंत्र के पास जोरदार धमाका! घटनास्थल से 50 किलोमीटर दूर तक दिखा असर

इस्लामाबाद,06 अक्टूबर 2023 । पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में शुक्रवार को विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी, जहां सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग स्थित है। विस्फोट का प्रभाव घटनास्थल से करीब पचास किलोमीटर दूर महसूस किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है।

हाल ही में हुए दो बड़े आत्मघाती विस्फोट

इससे कुछ ही दिन पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ही घंटों के भीतर दो आत्मघाती विस्फोट हुए थे। इन दोनों विस्फोटों में कम से कम 65 लोग मारे गए थे।बलूचिस्तान में विस्फोट एक मस्जिद के पास उस समय हुआ था। एक हमलावर ने पुलिस वाहन के पास विस्फोट कर दिया था, जहां लोग पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर जुलूस के लिए एकत्र हो रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी विस्फोट एक मस्जिद में हुआ था।

पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार

इसी साल सितंबर माह में अमेरिका के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि पाकिस्तान के पास अभी करीब 170 परमाणु हथियारों का भंडार है, जो वर्तमान विकास दर से 2025 तक बढ़कर 200 हो जाएंगे। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स में प्रकाशित न्यूक्लियर नोटबुक शीर्षक के लेख में वैज्ञानिकों ने कहा था कि हमारा अनुमान है कि पाकिस्तान के पास अब करीब 170 परमाणु हथियार हैं। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने 1999 में अनुमान लगाया था कि पाकिस्तान के पास 2020 तक 60-80 परमाणु हथियार हो जाएंगे लेकिन तब से कई नई हथियार प्रणालियों के विकसित होने से यह आंकड़ा आगे बढ़ गया है। न्यूक्लियर नोटबुक कॉलम, 1987 से एटॉमिक साइंटिस्ट बुलेटिन में प्रकाशित किया गया था। लेख के अनुसार, यह अनुमान अनिश्चित है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अपने परमाणु हथियारों की ज्यादा जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती है। अनुमान के लिए मीडिया रिपोर्ट्स, थिंक टैंक विश्लेषण और उद्योग प्रकाशन शामिल हैं। साथ ही सैटेलाइट तस्वीरों का भी विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान फिलहाल हर साल 14-27 नए हथियारों को बनाने लायक मैटेरियल का उत्पादन कर रहा है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान सालान औसतन 5-10 परमाणु हथियार बना रहा है। पाकिस्तान के 36 मिराज 3/4 और जेएफ17 विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। साथ ही भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें जिनमें अब्दाली, गजनवी, शाहीन, नस्त्र और मध्यम श्रेणी की गौरी और शाहीन-2 मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं।

पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सौंपी गई एंबुलेंस की चाभी,हरी झंडी दिखाकर एंबुलेंस को किया गया रवाना

बुढार के बाद पटना स्वास्थ्य केंद्र को मिली जिला पंचायत उपाध्यक्ष निधि से एंबुलेंस

आयोजित कार्यक्रम में उद्बोधन के दौरान प्रतिनिधियों व नेताओं ने इशारों इशारों में चलाया जुबानी बाण

जुबानी बाण के साथ दिखाई दिया अंदर खाने का आपसी मनमुटाव,सीएमएचओ को कार्यक्रम के दौरान विधायक की लगी फटकार

-रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर,06 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना में एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम वृहद बनाते हुए आयोजित किया गया था, यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा था, नहीं तो इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर जल्द भी खत्म किया जा सकता था, पर यह कार्यक्रम वृहद व भीड़ भाड़ कर के आयोजित किया गया था, जिससे अपनी उपलब्धियों को शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाया जा सके। यही वजह था कि कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों व नेताओं का आपसी जुबानी बाण भी एक दूसरे के लिए इशारे इशारों में चलते हुए सुना देखा गया, जिसे समझने वाले समझ भी रहे थे और ना समझने वाले सर खुजाते नजर आ रहे थे, पर कहीं न कहीं जुबानी बाण में आक्रोश भी खूब था जो समझ में भी आ रहा था,कार्यक्रम भले ही एकजुटता के साथ था पर वाणी में एक जुटता बिल्कुल नहीं थी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पटना को जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने दी एम्बुलेंस,बता दें की जिला पंचायत कोरिया उपाध्यक्ष वेदान्ती तिवारी ने अपनी नीधि से जिला पंचायत विकास निधि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुडार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस प्रदान की। इस अवसर पर नगर पटना के बड़ी तादाद में व्यापारी, पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामिणों की काफी संख्या उपस्थित रही। एम्बुलेंस की चाभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित अतिथियों ने स्वास्थ्य विभाग को सौंपी व हरी झंड़ी दिखाकर एम्बुलेंस को अतिथियों ने रवाना किया। इस

अवसर पर प्रमुख रूप से अशोक जायसवाल, शारदा दुबे, गुड्डन खान, रामाधार सोनी, उप सरपंच परेश सिंह, पंचायत सचिव कबीर दास, विजय सिंह, महेश साहू, मोती लाल गुप्ता, राजा शर्मा, सोनू राज यादव, निलेश पाण्ड़ेय, उदय सिंद्राम, ईश्वर दयाल सिंह, पूर्व सरपंच राकेश प्रताप सिंह, सुजीत सोनी, किशन तिवारी, प्रकाश पाण्डेय सहित काफी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, सदस्य व ग्रामीण उपस्थित थे।

सुविधा बढ़ाना नेक कार्य

कार्यक्रम में पहुंची संसदीय सचिव क्षेत्रीय विधायक अम्बिका सिंहदेव ने कहा कि यह एक नेक कार्य है, इस प्रकार के कार्यों में हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार होने से लोगों को बीमार लोगों को जल्द इलाज की सुविधा मिल सकेगी जो नेक कार्य है।

रनई जमींदार ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के कार्यों को लेकर की उनकी सराहना

रनई जमींदार योगेश शुक्ला ने एम्बुलेंस प्रदान करने को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदान्ती तिवारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बड़ी सोच का बड़ा जादू है, इस प्रकार के परोपकारी कार्यों में हम सभी को हिस्सा लेना चाहिए, यह मात्र एम्बुलेंस का लोकार्पण कार्यक्रम नहीं है यह उन भाई बहनों जो बीमार हैं उनकी जिन्दगी बचाने का अभियान है, कोई बीमार हुआ या दुर्घटनाग्रस्त हुआ और समय रहते उसे ईलाज मिला तो उसकी जान बचाई जा सकती है, पटना चौरासी बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह वाहन संजीवनी वाहन के रूप में काम आऐगा।उन्होंने यह भी कहा की जीवन में सबसे बड़ा पुण्य का काम है किसी के जीवन की रक्षा करना और यदि किसी ने एक भी जीवन की रक्षा की वह पुण्य का भागीदार अवश्य बनेगा। योगेश शुक्ला ने आगे कहा की अभी पितृपक्ष का शुभ समय चल रहा है और इस अवसर पर यह सौगात जो एंबुलेंस स्वरूप मिल सकी है वह संजीवनी का काम करेगी क्षेत्र के बीमार लोगों के लिए। उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान उपस्थित सभी लोगों का नाम मंच से लिया सभी का सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान उन्होंने बताया जिससे लोगों में भी उन्हे सुनने की उत्सुकता देखी गई।उन्होंने मंच को बांधे रखा जबतक वह कहते रहे लोग सुनते रहे।

क्षेत्र के हर वर्ग के लिए आएगी काम या एंबुलेंस, वेदांती तिवारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष

वेदान्ती तिवारी ने कहा कि क्षेत्र का कोई गरीब माता, पिता, भाई, बहन, असमर्थ व्यक्ति जो अस्पताल नहीं पहुंच सकता उसके लिए यह निःशुल्क व्यवस्था की गई है लोगों की जिन्दगी बचाने से बड़ा पुण्य कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। उन्होंने क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस की आवश्यता बताते हुए कहा की क्षेत्र बड़ा है और जरूरत समझकर ही उन्होंने जिला पंचायत निधि के सदुपयोग का विचार बनाया जो आज संभव हो सका है। उन्होंने कहा की आगे उनकी तरफ से और भी क्षेत्र हित जन हित सुविधाओं को लेकर प्रयास किए जाएंगे जिसमे क्षेत्रवासियों का भी सहयोग मार्गदर्शन जरूरी है।

स्वास्थ्य सेवा में बढ़ोतरी, गायत्री सिंह,सरपंच ग्राम पंचायत पटना

सरपंच गायत्री देवी सिंह ने कहा कि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और यह नगर पंचायत भी हो गया है,स्वास्थ्य सेवाऐं भी निरंतर अच्छी होती जा रही है, अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ईलाज के लिए यह एम्बुलेंस संजीवनी की तरह साबित होगी, सीएमएचओ आरएस सेंगर व बीएमओ बलवंत सिंह ने पटना में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार से बताया।

कुछ दिन पूर्व हुए मशीन उद्घाटन कार्यक्रम में क्यों नहीं जुटी थी लोगों की संख्या,इसको लेकर भी विधायक ने लगाई अस्पताल प्रबंधन की क्लासःसूत्र

बताया यह भी जा रहा है जिसकी पुष्टि नहीं हुई है की वेदांती तिवारी के द्वारा प्रदाय किए गए एंबुलेंस के तारतम्य में आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग जुटे थे वहीं इसके पूर्व ही एक कार्यक्रम और हुआ था अस्पताल में जिसमे एक मशीन का उद्घाटन हुआ था और जो उपलब्धि बतौर विधायक क्षेत्र सहित ग्राम जनों को बताने भी पहुंची थीं,लेकिन उस दिन ऐसी संख्या नहीं जुटी जैसी संख्या वेदांती तिवारी के एंबुलेंस प्रदाय करने के कार्यक्रम में जुटी, बताया जा रहा है इसको लेकर भी विधायक ने अस्पताल प्रबंधन की क्लास ली और नाराजगी जाहिर की।

वेदांती तिवारी ने पटना क्षेत्र में साबित की अपनी लोकप्रियता

जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने एंबुलेंस प्रदान करने के कार्यक्रम को गंभीरता से लिया और उन्होंने क्षेत्र के लोगों को बकायदा आमंत्रित किया। क्षेत्र के लोगों ने भी आमंत्रण स्वीकार किया और पहुंचे भी,इस अवसर पर पहली बार किसी कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के पटना चिकित्सालय में इतनी संख्या लोगों की नज़र आई,वहीं लोगों ने यह भी माना की यह एक कार्यक्रम है जो यादगार रहा वहीं एक कार्यक्रम जब जन औषधि केंद्र के उद्घाटन के दौरान किया गया था वह यादगार था। वेदांती तिवारी ने इस कार्यक्रम से यह साबित किया की पटना क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है जो लगातार बढ़ रही है।

एक बड़ी सोच से संभव

कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि यह एक बड़ी सोच है, अब गंभीर हालत के मरीजों को बड़े अस्पताल भेजने के लिए किसी अन्य वाहन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरीज व मरीज के परिजनों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम का संचालन विनोद शर्मा ने किया।

सीएमएचओ को फटकार

विधायक द्वारा दी गई एंबुलेंस को लेकर अस्पताल में ना रहने पर विधायक ने फटकार लगाते हुए मंच से ही पूछा कि आखिर कहां गई एंबुलेंस, जिस पर सीएमएचओ कुछ बोलने से बचते रहे और पता करने की बात कही।

मंच पर विधायक की मौजूदगी कांग्रेसजनों की मौजूदगी के बावजूद एकजुटता नजर नहीं आई

अवसर भले ही बड़ा था,क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि का था वहीं यह उपलब्धि भी प्रदान करने वाले कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ सदस्य थे मंच पर विधायक भी थीं अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी भी थे,सामने भी पार्टी के कार्यकर्ता थे वहीं ग्राम जन क्षेत्र जन थे लेकिन कांग्रेस पार्टी की एकजुटता कहीं गुम नजर आई। मंच पर जो लोगों ने देखा और जो वह बाद में चर्चा करते सुने गए उसके अनुसार भले ही एक ही दल के लोग एक साथ बैठे थे लेकिन उनके बीच की दूरियां साफ नजर आ रही थीं,आपस में उनका मनमुटाव साफ झलक रहा था उद्बोधन में भी यह झलक आया की कहीं न कहीं कोई न कोई कमी जरूर है एकजुट तो बिलकुल भी नजर नहीं आए कांग्रेसी। वैसे यह ऐसा अवसर था जहां उपलब्धियों के बखान मात्र की जरूरत थी पिछला क्या कब कैसे हुआ वह मौजूद है नहीं है यह विषय मंच से बोलने वाला नहीं था बाद में भी विषय पर चर्चा की जा सकती थी यह भी लोग कहते सुने गए।

कार्यक्रम के दौरान वेदांती तिवारी जिंदाबाद के लगे नारे

कार्यक्रम के दौरान वेदांती तिवारी जिंदाबाद के नारे लगे। लोगों ने उनके समर्थकों ने उनके द्वारा प्रदान की गई एंबुलेंस सुविधा के लिए उनका धन्यवाद जिंदाबाद के नारों के साथ किया।

क्षेत्रीय विधायक को तीन साल बाद आया उन्होंने दिया था पटना अस्पताल को एंबुलेंस,ली एंबुलेंस की उन्होंने सुध

कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक की नाराजगी भी देखने को मिली,उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के मुखिया से पूछा की उनके द्वारा जो एंबुलेंस तीन साल पहले दिया गया था वह कहां है,वहीं उन्होंने इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की क्योंकि उनके द्वारा प्रदाय किए गए एंबुलेंस की सुविधा नहीं मिलने की बात ग्रामीणों ने उनसे कही जैसा की सूत्रों का दावा है,वहीं विधायक की नाराजगी जो तीन साल पूर्व दिए गए एंबुलेंस को लेकर थी को लेकर यह भी लोगों ने कहा की तीन साल बाद उन्हें यह तब याद आ रहा है जब दूसरा कोई नया एंबुलेंस प्रदान कर रहा है वहीं इसके पहले उन्हे सुध लेने की जरूरत थी जो उन्होंने नहीं ली।

कोरिया वन मंडल में काट दिए गए डेढ़ सौ सरई के पेड़,क्या वन अमला कुंभकर्णी नींद में?

लाचार,बीमार रेंज अफसरों की पोस्टिंग ही वनों की सुरक्षा में बाधाःडीएफओ

-रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर,06 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत ही दुखद समाचार है और पर्यावरण संरक्षण पर बड़ा आघात भी। जानकर हैरानी होगी की कोरिया वन मंडल अंतर्गत सोनहत वन परिक्षेत्र के भगवतपुर में ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से वनाधिकार न मिलने के विरोध में 40,50 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा करते हुए लगभग 150 साल के बड़े वृक्षों को काटकर गिरा दिया गया है। मौके में हुए इस हृदय विदारक वनों की विनाशलीला पर जहां वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने बताया की अवैध कटाई के दौरान कुछ वन कर्मी मौके पर पहुंचे थे परंतु उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।आपको बता दें की जहां पर इतने बड़े पैमाने पर एक तरफ से डेढ़ सौ राष्ट्रीय कृत साल वृक्षों की बेधड़क कटाई हो गई और वन कर्मी वनों की विनाशलीला का दीदार करके लौट आए न तो पी.यू.आर. की कार्यवाही की और न तो विभाग के उच्चाधिकारियों को खबर की गई। हालांकि वनों की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही का कोई भी एक जिम्मेदार नहीं है बल्कि सोनहत रेंज अफसर

भी बराबर जिम्मेदार हैं।ये इसलिए क्योंकि उक्त रेंजर बिना विभाग को सूचना दिए ही मुख्यालय से सरकारी गाड़ी के साथ हफ्तों नदारद रहने के आदि हैं जिसको लेकर कोरिया वन मंडल की डीएफओ द्वारा पत्रकारों के सामने कहा भी गया की 10 कदम चलने पर बीमार पड़ जाने वाले बीमारू रेंज अफसरों की पोस्टिंग ही वनों की सुरक्षा में बाधक बन कर रह गए हैं।साथ ही उन्होंने यह भी कहा की मेरे द्वारा राजधानी स्तर पर बैठे अफसरों तक इस बात को पहुंचाया जाएगा की ऐसे में हम आई एफ एस अपना काम कैसे कर पाएंगे।अपने वक्तव्यों पर डीएफओ ने बताया की आप पत्रकार लोग हमे सूचना देने से पहले कटते वनों की रक्षा किया कीजिए।जिसका मतलब सीधी तौर पर है की पत्रकार डेढ़ सौ कटे वृक्षों की चौकीदारी करें और वन अमला निर्माण कार्य के भ्रष्टाचार में लिप्त रहें।

पूरे इंडिया में जंगल कट रहे तो यहां का जंगल कटना ताज्जुब कैसे?

जी हां कोरिया वन मंडल के डी एफ ओ द्वारा कुछ वक्तव्यों को कहा गया जो की इनकी जिम्मेदारी और दायित्व को गैरजिम्मेदाराना साबित करता है।सोनहत रेंज के तंजरा और कछाड़ी सर्किल के मुनारों के दोनो ओर एक चक्क काटे गए सैकड़ों सरई के विशाल वृक्षों पर वजह जानने पर डीएफओ द्वारा अपनी भूमिका पर कुछ कहने की बजाय उन्होंने कहा की जंगल तो पूरे इंडिया में कट रहे हैं तो कोरिया वन मंडल में जंगल कटना ताज्जुब की बात नहीं।उन्होंने कहा की आप पत्रकार लोगों से जानकारी मिली है मै जांच करूंगी।जिसके बाद मामले पर बाइट लेने पहुंचे पत्रकारों ने डीएफओ की प्रतिक्रिया जाननी चाही तो डीएफओ ने कैमरे के सामने आने और कुछ कहने से इंकार कर दिया।जंगल कटने की सूचना पत्रकारों द्वारा मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वन वृत सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक और डी एफ ओ को चार दिन पहले ही दी जा चुकी थी बावजूद इसके राजधानी से लेकर वन वृत या वन मंडल स्तर पर कोई भी जांच या कार्यवाही नहीं की गई जो इस बात को दर्शाता है की भूपेश सरकार में वन अफसरों की मनमानी चरम पर पहुंच चुकी है शायद तभी जंगलों की बेरोक टोक अवैध कटाई सहित वन्य प्राणियों की तस्करी को खुली छूट मिल चुकी है।

मनेद्रगढ़ बस स्टैंड मुख्य मार्ग पर थोक एवं फुटकर व्यापारियों ने किया कब्जा

-संवाददाता-
मनेन्द्रगढ़,06 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

बस स्टैंड के मुख्य मार्ग पर स्थानीय थोक एवम फुटकर व्यापारियों के साथ ही सड़क पर लगने वाले ठेलों के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. सड़क में दिनभर 12 चक्का ट्रक और दर्जनों पिकअप छोटा हाथी खड़े रहते हैं जिसके कारण यात्रियों सहित आम नागरिकों का आवागमन बड़े मुश्किल में हो रहा है पूरे बस स्टैंड के आसपास जाम की स्थिति निर्मित हो रही है दिन में कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है बस स्टैंड के समीप ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है स्थानीय वार्ड वासियों ने पुलिस प्रशासन सहित नगरी निकाय के जिम्मेदार अधिकारियों को इस अव्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। विदित हो कि मनेंद्रगढ़ बस स्टैण्ड से प्रतिदिन सैकड़ो बसों का प्रदेश एवं प्रदेश के बाहरी भागों में संचालन होता है प्रतिदिन कई दर्जन बसें और सैकड़ों यात्री इन बसों से अपने गंतव्य स्थान तक आते जाते रहते हैं , लेकिन पिछ्ले कुछ दिनों से व्यापारियों ने वहां पर अपना गल्ला सहित अन्य सामग्रियों का थोक व्यवसाय प्रारंभ कर लिया है जिस कारण उनके बड़े-बड़े ट्रक गोदाम में खाली होते रहते हैं और फिर वहां से आसपास के क्षेत्र में छोटी पिकअप से माल भेजा जाता रहता है वही शाम होते ही दर्जन भर बिरयानी अंडा फल के ठेले भी इन मार्गो पर अपना आधिपत्य बना रखे हैं बस स्टैंड मोड पर एक चर्चित समोसा आलू गुंडा दुकान के लगने से भी काफी भीड़ बनी रहती है आए दिन जम के कारण लोगों को अपना समय बर्बाद करना पड़ता है कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है जिस कारण राहगीर भी काफी परेशान हो रहे हैं स्थानीय लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए कई बार वार्ड के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से भी मांग की है लेकिन अभी तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो सका है जनप्रतिनिधियों ने भी अभी तक कोई पहल नहीं की है बस स्टैंड मार्ग पर अतिक्रमण कर खड़े ट्रक पिकअप छोटा हाथी सहित अन्य टैक्सियों के कारण आवागमन के कारण सुबह 8ः00 बजे से शाम 8ः00 बजे तक यह मार्ग पूरी तरह से बंधित हो जाता है स्थानीय बस व्यवसाईयों सहित बस संचालकों ने पुलिस प्रशासन सहित नगरीय निकाय के जिम्मेदार अधिकारियों से अपील करते हुए अतिक्रमण कारियो से निजात दिलाने की मांग की है साथ ही अव्यवस्थित ढंग से लगे पिकअप ट्रक एवं अन्य मालवाहकों को रात में लोडिंग अनलोडिंग कराए जाने की मांग की है।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव

शासकीय भूमि से कब्जा हटाने दिया ज्ञापन

मोटरसाइकल रैली निकालकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय एमसीबी गोंड वाना गणतंत्र पार्टी नेता व कार्यकर्ता

महामहीम राष्ट्रपति, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन,पांच सूत्रीय मांगो का है ज्ञापन

ज्ञापन में विधायक प्रतिनिधि भरतपुर सोनहत साथ ही प्रेस क्लब अध्यक्ष एवम साथियों द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे को खाली कराने की है मांग

शहर के शासकीय चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की है मांग

विधायक के गृहग्राम में वन भूमि को नियम विरुद्ध तरीके से पट्टे की भूमि बनाए जाने को लेकर भी विरोध में सौंपा गया है ज्ञापन

शासकीय भूमि वन भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की भी की गई है मांग

-रवि सिंह-
एमसीबी,06 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला एमसीबी ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 4 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय नवीन जिला एमसीबी का घेराव किया और मोटरसाइकल रैली निकालकर वह घेराव करने पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय घेराव करने पहुंचे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जो कलेक्टर एमसीबी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति साथ ही राज्यपाल को प्रेषित किया जाएगा जिसमे यह मांग की गई है की एमसीबी नवीन जिले में शासकीय भूमि पर जो कब्जा लगातार दर्ज कराया जा रहा है जिस तरह शासन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए शासकीय भूमि , वन भूमि का पट्टा बनवाने का प्रयास किया जा रहा है उसे रोका जाए और ऐसे लोगों पर प्राथमिकी

दर्ज करते हुए कार्यवाही की जाए जो शासकीय भूमि वन भूमि पर कब्जा दर्ज कर रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वहीं ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग की है की शहर के चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाए।

पांच सूत्रीय मांगें जिनको लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किया कलेक्टर कार्यालय एमसीबी का घेराव

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कठौतिया से वाहन रैली निकालकर जिला अध्यक्ष केवल सिंह मरकाम के नेतृत्व में एवं समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता की उपस्थिति में जिला कलेक्टर कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौपा, दिनांक 04/10/2023 को गोडवाना गणतन्त्र पाटी, जिला एमसीबी द्वारा जनहित के विभिन्न मांगों को लेकर व शासकीय भूमि पर नियम विरुद्ध व अवैध तरीके से कब्जा को तत्काल हटाने को लेकर वाहन रैली कलेक्टर का घेराव करते हुए महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर एमसीबी ज्ञापन को सौपा प्रमुख मांगे इस प्रकार है। ग्राम चैनपुर स्थित शासकीय भूमि पर नियम विरुद्ध तरीके से लोगों द्वारा कब्जा किया गया है जिसे तत्काल जांच कर हटाया जाए एवं उनके विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज कि जाए ।, विवरण इस प्रकार है रंजीत सिंह प्रेस क्लब अध्यक्ष एम. सी.बी. खसरा नं. 83/1 रकबा 3.5780 हेक्टे ग्राम चैनपुर 7धीरेन्द्र विश्वकर्मा, खसरा नं. 83/1 रकबा 3.5780 हेक्टे ग्राम चैनपुर, मो. अकील खसरा नं. 83/1 रकबा 3.5780 हेक्टे ग्राम 2- टोल नाका महाराजपुर नागपुर में ग्राम लोहारी व आसपास गाव के लोगों की परेशानी का निराकरण तत्काल कराया शासकीय शराब को एन.एच से तत्काल हटाया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ में स्त्री रोग विशेषज्ञ कि नियुक्ति कि जाए। यह कि वर्तमान विधायक के गृह ग्राम साल्ही में अवैध व नियम विरुद्ध तरीके से शासकीय व जंगल कि भूमि पर पट्टे के लिए उच्च कार्यालय में प्रेषित किया गया है। जिसका मामला एस.डी.एम कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में चल रहा है विचाराधीन है। विवरण इस प्रकार है।पवन सिंह स्व. राम खेलावन अध्यक्ष वनाधिकार समिति साल्ही खसरा क्र. 02 रकबा 0.34 है, सुरजीत सिंह कमरों / आनंद सिंह कमरो (विधायक का छोटा भाई) खसरा क्र. आर.एफ. 710 का 0.185 है। जगरनाथ सिंह कुंज सिंह (सरपंच जी का छोटा भाई व कृषक मित्र सालही) खसरा क्र. आर.एफ 710 रकबा 02/01 अतः निवेदन है कि कंडिका 1 से 5 तक कि समस्त मांगों को तत्काल कार्यवाही कर समस्या का समाधान किया जाए, गोडवाना गणतन्त्र पार्टी अपेक्षा करती है यह भी पार्टी ने अपने ज्ञापन में लिखा है।

विधायक प्रतिनिधि प्रेस क्लब अध्यक्ष सहित अन्य पर लगाया है शासकीय भूमि पर कब्जा करने का आरोप

भरतपुर सोनहत विधायक के प्रतिनिधि साथ ही प्रेस क्लब के अध्यक्ष एमसीबी व अन्य ने शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किया है वहीं यह कब्जा शासन सत्ता के दबाव से संभव बनाया है उनके द्वारा यह आरोप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगाता चला आ रहा है।गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मामले में लगातार मुखर होकर विरोध कर रहा है और विधायक प्रतिनिधि प्रेस क्लब अध्यक्ष सहित अन्य के कब्जे से शासकीय भूमि मुक्त कराने के अभियान में है। वहीं इस मामले में प्रमुख मुद्दा यह है की क्या शासकीय भूमि पर विधायक प्रतिनिधि का कब्जा प्रशासन जायज मान रहा है क्योंकि वह सत्ताधारी दल के विधायक के प्रतिनिधि हैं प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या सफल होगी अपने अभियान में,क्या एमसीबी नवीन जिले में अवैध रूप से शासकीय जमीन पर हो रहा कब्जा होगा खाली

एमसीबी नवीन जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शासकीय भूमि पर जारी अवैध कब्जे को लेकर आंदोलनरत है,पार्टी विधायक प्रतिनिधि प्रेस क्लब अध्यक्ष सहित कई अन्य पर सबूत सहित आरोप लगा रही है की उनके द्वारा शासन सत्ता का दुरुपयोग कर शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा है और सभी मामलो में पट्टा लेने के फिराक में हैं कब्जाधारी,पार्टी ने इसको लेकर पहले चेतावनी दी प्रशासन को फिर पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और बाद में राष्ट्पति सहित राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले में उचित कार्यवाही की मांग की कब्जा खाली कराने की मांग की। अब देखना है की क्या अभियान में सफल होगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या सत्ता शासन की आड़ में पत्रकारिता की आड़ में कब्जा करने का खेल जारी रहेगा।

क्या शासन सत्ता का दुरुपयोग कर कोई भी शासकीय भूमि पर कब्जा कर सकता है,क्या पत्रकार को भी शासकीय भूमि पर कब्जा करने का अधिकार है?

एमसीबी नवीन जिले में जिस तरह एक मामला सामने आया है जिसमे प्रेस क्लब अध्यक्ष साथ ही विधायक प्रतिनिधि वहीं अन्य के द्वारा जिस तरह शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा और प्रशासन पर जैसा की आरोप है वह शासन सत्ता के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है चाहकर भी, ऐसे में सवाल यह उठता है की क्या शासन सत्ता एस जुड़कर प्रेस से जुड़कर शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा सकता है,वैसे बताया जा रहा है की यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो जिले में अवैध कब्जे के लिए और भी राजनीतिक दल से जुड़े लोग सामने आ सकते हैं और जगह जगह कब्जा कर सकते हैं जो प्रशासन के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

कटघोरा पुलिस ने मंदिर से जेवर चोरी करने वाले चोरों पर की कार्यवाही

-संवाददाता-
कोरबा,06 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

कटघोरा थाना में अपराध क्रमांक 391 / 2023 धारा 457, 380, 34 भादवि के प्रार्थी गिरधारी अग्रवाल पिता स्व. रतिराम उम्र 59 साल साकिन कटघोरा दिनांक 05.10.2023 को थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि राधासागर तालाब किनारे हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर, हनुमान की मूर्ति के उपर लगे लगभग 100 ग्राम चांदी के छत्र को दिनांक 03.10.2023 के रात्रि अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध कायम कर विवचेना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक यू उदय किरण (भापुसे) के निर्देशन, एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा तथा अनु0 अधि0 कटघोरा पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना

प्रभारी निरीक्षक तेजकुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर पतासाजी कर आरोपी(1) सुनील रात्रे पिता भुवनलाल उम्र 38 साल जाति सतनामी साकिन मेलाग्राउंड तहसीलभाठा कटघोरा थाना कटघोरा (2) तरूण कुमार राठौर पिता कन्हैयालाल उम्र 32 साल जाति नायक साकिन टिंगीपुर कटघोरा थाना कटघोरा को पकड़ा गया । जिनके कब्जे से चोरी गई चांदी का छत्र कटा हुआ, किमती लगभग 10,000/- रू. को जब्त कर विधिवत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक तेजकुमार यादव, सउनि विनोद खाण्डे, प्रआर 334 संदीप पाण्डेय, आर 364 अजय खुटले, आर 517 महेन्द्र चन्द्रा, आर 536 खम्हन सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

ग्रामीण यांत्रिकी उप संभाग कार्यालय खड़गवां की कुर्सी पर पदस्थ एसडीओ का मोह नहीं जा रहा है वर्षों से,एक ही जगह पर जमे हुए हैं अंगद के पैर की तरह

-राजेन्द्र शर्मा-
खड़गवां,06 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

ग्रामीण यांत्रिकी विभाग उप संभाग कार्यालय खड़गवां की कुर्सी से लगता है पदस्थ एस डी ओ का मोह नहीं जा रहा है, जो उप अभियंता से एसडीओ तक का सफर तय करने वाले एसडीओ पिछले चौदह पंद्रह वर्षो से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर अंगद के पांव की तरह जमे हुए है। जबकि पूर्व एवं वर्तमान राज्य शासन द्वारा समय- समय पर शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों की सर्जरी की जाती रही है।

सत्ता पक्ष के अपने आकाओं की जी हुजूरी करके अपना पोस्टिंग खड़गवां कराने में सफल रहे, और इस प्रकार लगभग 14- 15 वर्षो से एक ही स्थान पर वे जमे रहकर खड़गवां ग्रामीण यांत्रिकी विभाग उप संभाग की कुर्सी को अपना स्थाई अड्डा बना रखे है। शायद शासन- प्रशासन ने भी इस ओर ज्यादा ध्यान देना मुनासिब नही समझा, जिसके कारण ये बड़े ढिठ किस्म के हो चले हैं साथ ही ग्राम पंचायतों में होने वाले अनेक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी ग्रहण लगाते चले

आ रहे है।

जैसे अजगर को उसके जगह से हटाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक उसी किस्म के एसडीओ साहब लगते है। तथा लगता है इनको खड़गवां ग्रामीण यांत्रिकी विभाग उप संभाग का हवा-पानी कुछ ज्यादा ही भा गया है, इसीलिए खड़गवां का मोह नही छोड़ पा रहे है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि एसडीओ साहब को यहां मन मुताबिक निर्माण कार्य का कमीशन भी धड़ल्ले से वसूल किया जा रहा है प्रत्येक निर्माण कार्य की फाइल में दस से बीस हजार रुपए की वसूली का खेल जारी है खड़गवां ग्रामीण यांत्रिकी विभाग उप संभाग कार्यलय में बिना कमीशन के कोई भी निर्माण कार्य की फाइल हिलती तक नहीं है छूना तो दूर की बात है जब तक कमीशन की राशि नहीं मिलती फाइल पड़ी धूल खाती है मनरेगा के निर्माण कार्य और अन्य योजनाओं के तहत हुए निर्माण कार्यो की सी सी जारी करने धड़ल्ले से कमीशन कि वसूली होती है जो अन्य जगह में शायद नहीं मिले।

ग्रामीण यांत्रिकी विभाग उप संभाग कार्यलय में जब भी जाएंगे तो अन्य कर्मचारियों का जवाब रहता है कि साहब फिल्ड में गए हुए है कहां..गए है पता नही..! आखिर एसडीओं साहब इतना फिल्ड करते कहां- कहां है जो ज्यादातर कार्यालय में दिखते नही.. छोड़िए एसडीओं साहब है? कुछ भी कर सकते है। फिलहाल वे वर्षो से एक ही स्थान में पदस्थ है। जबकि शासन के नियम अनुसार उनका स्थानांतरण कब का हो जाना था। लेकिन इनको अभयदान मिलता आ रहा है। शासन-प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है। क्योंकी एसडीओं अगर 14- 15 वर्षो से एक ही जगह पर रह सकते है तो अन्य अधिकारी- कर्मचारी क्यों नहीं रह सकते ? क्या चुनाव आयोग के द्वारा इस तरह चौदह से पंद्रह सालों से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारीयों को क्यों नहीं हटाया जा रहा हैं ?

बालको के माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन प्रशिक्षण से कोरबा में बढ़ी जागरूकता

-संवाददाता-
कोरबा,06 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने अपनी नई किरण परियोजना के अंतर्गत माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन पर दो दिवसीय जिला-स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। सार्थक जन विकास संस्थान और कोरबा के जिला शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को अपने संबंधित स्कूलों में माहवारी के प्रति संवेदनशील बनाने, सहायकपूर्ण एवं सहज वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता प्रदान करना है। सामाजिक कार्यकर्ता और अनुभवी एमएचएम विषय विशेषज्ञ श्री ओम प्रकाश गायरी ने दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान विस्तृत परिचर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में माहवारी चक्र को समझना एवं भ्रांतियों पर चर्चा के साथ विभिन्न समस्याओं को शामिल किया गया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव और माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को इस दौरान साझा किया। माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन प्रशिक्षण में, विशेष रूप से दिव्यांग लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था जिसमे माहवारी को स्वच्छता प्रबंधन और गरिमा के साथ जोड़कर उनके लिए उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने पर कार्य किया गया। बालको के दृष्टिबाधित और मूकबधिर बच्चों के लिए आयोजित विशेष सत्र में मॉड्यूल सत्र शामिल थे। यह दिव्य ज्योति स्कूल में हुआ, जिसमें जिले के 5 से अधिक बच्चे शामिल हुए।

बालकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री राजेश कुमार ने कहा कि यह पहल समावेशी और संवेदनशील समाज को बढ़ावा देने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारे शिक्षक माहवारी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आवश्यक उत्पादों की जानकारी, माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन से छात्राओं को सशक्त बना रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही माहवारी संबंधी भ्रांतियों और शंकाओं को खत्म करना है। यह सिर्फ एक कार्यशाला नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का उद्घोष है। एमएचवी जागरूकता अभियानों के निरंतर संचालन के जरिए समाज में माहवारी के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के प्रति बालको प्रबंधन कटिबद्ध है।

विद्युत कंपनी के 10000 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा

-संवाददाता-
कोरबा,06 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा नई पेंशन सेवा अंतर्गत आने वाले विद्युत कंपनी के 10000 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की गई है, इस हेतु मैं हमारे विद्युत कंपनी के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 10000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के रुप में दी गई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी एक अमूल्य तोहफा है, मैं मुख्यमंत्री जी को आप सभी की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। ऊर्जा धानी कोरबा में छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के 3000 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी परिवार पुरानी पेंशन से लाभान्वित होंगे, इस निर्णय से कर्मचारी परिवार को पेंशन प्राप्त होने से उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलने के साथ साथ उनका भविष्य सुनहरा एवं खुशहाल होगा। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी ने इस हेतु बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश में लाखों कर्मचारी नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर आंदोलित हैं, कांग्रेस ही गरीब, मजदूर किसान के लिए हमेशा संवेदनशील रही है, इसी कारण कांग्रेस शासित राज्यों में सत्तारूढ़ होते ही पुरानी पेंशन की बहाली सरकार द्वारा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणा से अब तक तीन लाख से अधिक कर्मचारी परिवार को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी, नई पेंशन में उन्हें शेयर बाजार आधारित बहुत

ही कम पेंशन प्राप्त होने की स्थिति थी, लेकिन पुरानी पेंशन में सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतन का आधा पेंशन के रूप में प्राप्त होगा, इससे उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा, जीवन यापन में कठिनाई ना होकर उनका भविष्य सुखद होगा। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने उत्पादन कंपनी के कोरबा क्षेत्र में पदस्थ सभी अधिकारी, कर्मचारी परिवार को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं, उन्होंने कहा है कि विद्युत कंपनी परिवार के साथी एवं संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के लिए जब भी मुझसे संपर्क किया है मैने उन्हें पदोन्नति, नियुक्ति व पुरानी पेंशन के मामले में भी पहल कर सहयोग दिया है, मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त कर विद्युत कंपनी के सभी अधिकारी कर्मचारी परिवार को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

बांगलादेश को हराकर फाइनल में पहुंचा भारत

» तीरंदाजी में महिलाओं ने जीता कांस्य पदक

हांगझोउ,06 अक्टूबर 2023। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में शुक्रवार को भारत ने तिलक वर्मा के 26 गेंदों में नाबाद 55 रनों की आतिशी पारी और वॉशिंगटन सुंदर की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत बंगलादेश को नौ विकेट से हरा कर फाइनल में पहुंच गया है। इसी के साथ इस स्पर्धा में भारत का कम से कम रजत पदक पक्का हो गया है। चीन में खेले जा रहे एशियाई खेलों में आज पुरूष क्रिकेट मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। बंगलादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 96 रन बनाए।

भारत ने 97 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हालांकि शून्य के स्कोर पर अपना पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गंवा दिया था। यशस्वी जायसवाल को रिपोन मोंडल ने मृत्युंजय चौधरी के हाथों कैच कराया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने पारी संभाली है। दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विकेट के चारों ओर रन बटोरे। दोनों के बीच हुई 95 रनों की साझेदारी ने भारतीय टीम को 9.2 ओवर में आसानी से जीत दिला दी। बंगलादेश की ओर से रिपोन मोंडल को 26 रन देकर एक विकेट मिला।

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए बंगलादेश ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 96 रन बनाए। बंगलादेश की ओर से सबसे अधिक नाबाद 24 रन जाकिर अली ने बनाए तथा परवेज हुसन ने 23 रन का योगदान दिया। इन दोनों के अलावा सिर्फ राकिबुल हसन 14 रन ही दहाई का आंकड़ा पार कर पाए। बंगलादेश के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए इनमें से उसके दो बल्लेबाज ज़ाकिर हसन और रिपोन मोंडल शून्य पर पवेलियन लौट गये। हसन को सुंदर ने जायसवाल के हाथों कैच आउट कराया।

वहीं मोंडल अर्शदीप की गेंद पर रिंकू ने कैच आउट किया। बंगलादेश को पहला झटका पांचवें ओवर में महमुदुल हसन जॉय पांच रन के रूप में लगा। उन्हें साई किशोर की गेंद जायसवाल कैच आउट किया। 21 रन के स्कोर पर बांग्लादेश का दूसरा विकेट कप्तान सैफ हसन एक रन के रूप में गिरा। वह सुंदर की गेंद पर रिंकू को कैच थमा बैठे। परवेज हुसैन 32 गेंद में 23 रन बनाकर आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज रहे। उन्हें तिलक वर्मा ने उन्हें ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच कराया। साई किसोर ने अफीफ हुसैन को सात रन के स्कोर पर आउट किया। शिवम दुबे ने उनका कैच पकड़ा। दुबे मैच में तीसरा विकेट झटका।

मृत्युंजय चौधरी 11 गेंद में चार रन के रूप में बंगलादेश ने अपना सात विकेट गवायां। उन्हें रवि बिश्नोई ने विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच कराया। उसके बाद राकिबुल हसन छह गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए हैं। उन्हें शाहबाज अहमद ने तिलक वर्मा के हाथों कैच कराया। रिपोन मंडल को शून्य पर अर्शदीप ने रिंकू के हाथों कैच आउट करा कर बंगलादेश की टीम को नौ विकेट पर 96 रन पर समेट दिया।

भारत की ओर से रवि साई किशोर ने तीन विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर को दो विकेट मिले। अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई और शाहबाज अहमद को एक-एक विकेट मिले।

वहीं, अंकिता, सिमरनजीत और भजन की भारतीय जोड़ी ने वियतनाम को हराकर महिला रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। आज यहां हुए कांस्य पदक मुकाबले में भारत की पांचवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने वियतनाम की डो थी आन एनगुएट, एनगुएन थी थान नी और हाओंग फुओंग थाओंग की टीम को 6-2 (56-52, 55-56, 57-50, 51-48) से हरा कर कांस्य पदक जीता।

इससे पहले, भारतीय टीम को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 6-2 से हार मिली थी। इसके बाद आज भारत को वियतनाम के साथ कांस्य पदक मुकाबला में जीत हासिल हुई।

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने नेपाल को रौंदा

» गोल्ड मेडल के लिए चीनी ताइपे से मुकाबला

हांगझोउ ,06 अक्टूबर 2023। शुक्रवार को भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में नेपाल को हरा दिया। इसके साथ ही टीम ने एशियन गेम्स फाइनल में जगह बनाते हुए कम से कम एक और सिल्वर पक्का कर दिया है। ऋतु नेगी की अगुवाई में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल को 61-17 के बड़े अंतर से हराया है। वहीं हाफ टाइम के समय भारतीय टीम 29-10 से आगे थी। जिसके बाद खेल शुरू होने पर भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए 61-17 से जीत दर्ज की।

भारतीय रेडर्स ने 9 बोनस अंक जुटाए जबकि डिफेंडर्स ने पांच ऑल आउट किया। भारत शनिवार को गोल्ड मेडल मुकाबले में चीनी ताइपे से भिड़ेगा, जिसने उलटफेर करते हुए दूसरे सेमीफाइनल में ईरान को 34-24 से मात दी।

इससे पहले भारतीय महिला टीम ने फाइनल तक पहुंचने के लिए तीन मैचों में जीत हासिल की है। उन्होंने सबसे पहले चीनी ताइपे से 34-34 से टाई खेला। उसके बाद साउथ कोरियाई टीम को 56-23 से हराया। फिर थाईलैंड को 54-22 से मात देकर आखिर में नेपाल को सेमीफाइनल मुकाबले में रौंद दिया।

चोटिल मेसी विश्व कप क्वॉलीफायर के लिए अर्जेंटीना टीम में शामिल

ब्यूनस आयर्स ,06 अक्टूबर 2023। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने बताया कि लियोनल मेसी को इस महीने के अंत में पराग्वे और पेरू के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर के लिए अर्जेंटीना की टीम में नामित किया गया है।

अर्जेंटीना के कप्तान को एक अज्ञात मांसपेशी की चोट के बावजूद शामिल किया गया है, जिससे 36 वर्षीय इंटर मियामी फॉरवर्ड को मेजर लीग सॉकर क्लब के पिछले चार मैचों से बाहर रखा गया था।

अर्जेंटीना के मैनेजर लियोनल स्कालोनी ने पांच अनकैप्ड खिलाड़ियों,मार्कोस पेलेग्रिनो, लुकास एस्क्विवेल, कार्लोस अल्कराज, ब्रूनो जैपेली और फाकुंडो फारियास को बुलाया, लेकिन 34 सदस्यीय टीम में चोटों से उबर रहे एंजेल डी मारिया और लिसेंड्रो मार्टिनेज को शामिल नहीं किया गया है।

अर्जेंटीना 12 अक्टूबर को ब्यूनस आयर्स में पराग्वे से और पांच दिन बाद लीमा में पेरू से भिड़ेगा।

मौजूदा विश्व चैंपियन ने फुटबॉल के शोपीस टूर्नामेंट के 2026 संस्करण के लिए अपने क्वालीफाइंग अभियान की शुरुआत सितंबर में इक्वाडोर और बोलीविया पर जीत के साथ की थी।

भारत ने पाकिस्तान को 61-14 से रौंदा

गोल्ड मेडल मैच में बनाई जगह

हांगझोउ ,06 अक्टूबर 2023। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 61-14 को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। वहीं अब भारतीय टीम फाइनल में चीनी ताइपे या ईरान से भिड़ेगी।

वहीं मुकाबले की बात करें तो, भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पाकिस्तान के डिफेंडर्स ने पहले कप्तान पवन सेहरावत और फिर असलम इनामदार को टैकल किया। जिसके बाद रेडिंग में उन्होंने विशाल और नितेश को आउट करके भारतीय टीम को बैकफुट पर भेज दिया। नवीन ने अपनी 4 रेड में 6 प्वॉइंट्स हासिल करते हुए भारतीय टीम को लीड दिलाई। सातवें मिनट में नवीन ने पाकिस्तान के बचे हुए दोनों डिफेंडर्स को आउट करते हुए उन्हें ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ भारत की लीड 11-4 की हो गई। पवन सेहरावत ने भी 9वें मिनट में अपना खाता खोला और इसके बाद एक सुपर रेड की और अपनी अगली रेड में एक पॉइंट हासिल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला। असलम ने 12वें मिनट में अपना पहला पॉइंट हासिल किया और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम दूसरी बार ऑल आउट हो गई।

इसके बाद भारत ने पकड़ को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने दिया और पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया। नवीन ने इस बीच अपना सुपर 10 भी पूरा किया और भारत की वापसी में उनका अहम योगदान था। 18वें मिनट में भारत ने तीसरी बार पाकिस्तान को लोना दिया और लगभग उन्हें मैच से बाहर कर दिया।

दूसरे हाफ में सचिन ने अपनी पहली रेड में ही टच पॉइंट हासिल किया। लेकिन वो अपनी अगली ही रेड में आउट हो गए। असलम इनामदार ने इस बीच लगातार अपनी रेडिंग में पॉइंट्स हासिल किए। सचिन तंवर तीन की डिफेंस में रेड करने गए, लेकिन वो यहां पर सुपर टैकल हो गए और पाकिस्तान को दो पॉइंट्स मिले। दूसरेहाफ में असलम इनामदार ने शानदार किया और पाकिस्तान के डिफेंस को सेटल नहीं होने दिया। भारतीय टीम एक बार फिर पाकिस्तान टीम को ऑल आउट करने के करीब आ गई और आखिरकार सचिन को भी रेड में पॉइंट मिला।

कुल मिलाकर इस मैच में भारत ने पाकिस्तानी टीम को 6 बार ऑल आउट किया। आखिर में आसानी के साथ भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया।

एचएस प्रणय को कांस्य पदक से करना पड़ा संतोष

हांगझोउ ,06 अक्टूबर 2023। भारत के एचएस प्रणय ने एशियाई खेलों के पुरुष एकल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में शुक्रवार को यहां विश्व रैंकिंग में 7वें नंबर के खिलाड़ी चीन के ली शिफेंग से 0-2 से हारने के बाद कांस्य पदक जीता। प्रणय 16-21, 9-21 के स्कोर से हारे।

एक कठिन मुकाबले में, प्रणय नेट्स पर तेज दिख रहे थे, लेकिन पीठ दर्द से जूझ रहे थे और रक्षा में कमजोर थे, क्योंकि चीनी खिलाड़ी ने अपने स्ट्रोक से उनका परीक्षण किया और उन्हें झुका दिया।

प्रणय रिटर्न के मामले में धीमे थे और नेट तथा लाइन दोनों में त्रुटि की संभावना अधिक थी। पहला गेम शुरू में एक करीबी मुकाबले की तरह लग रहा था, लेकिन चीनी खिलाड़ी ने कोर्ट के चारों ओर जोरदार स्मैश से अपनी जीत सुनिश्चित कर ली।

इससे पहले, 31 वर्षीय खिलाड़ी ने 21-16, 21-23, 22-20 से जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की और 1982 में सैयद मोदी के कांस्य पदक के बाद पुरुष एकल में भारत के लिए पहला पदक पक्का किया।

भारत की शीर्ष क्रम की पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी भी दिन में सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे।

एशियन गेम्स 2023 में भारतीय एथलीट्स के साथ धोखा कर रहा चीन

» पहले ज्योति और फिर नीरज-जेना बने शिकार

हांगझोउ ,06 अक्टूबर 2023। हांगझाऊ में 19वें एशियन गेम्स 2023 जारी हैं। लेकिन इतने बड़े इवेंट का मेजबान देश चीन लगातार अपनी धोखेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। जिस चीन को अपनी तकनीक पर गुरूर था, वही तकनीक एशियाई खेलों में उसका मजाक उड़ा रहा है। वहीं चीन के धोखेबाजी का शिकार सबसे ज्यादा भारतीय एथलीट्स हो रहे हैं, मेजबान देश लगातार किसी ना किसी कारण भारतीय एथलीट् को अपनी चाल में फंसा रहा है। इस कड़ी में सबसे पहले भारतीय धाविका ज्योति याराजी और उसके बाद भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा और किशोर कुमार जेना के साथ चीनी अधिकारियों ने बेईमानी की कोशिश की, लेकिन भारतीय एथलीट्स भी कहां पीछे रहने वाले थे सभी ने अपने जुनून के आगे धोखेबाज मेजबान देश की एक ना चलने दी।

भारतीय एथलीट्स के साथ धोखेबाजी

इन तीनों ही भारतीय एथलीट्स ने मेडल जीतकर चीनी अधिकारियों और तकनीक का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बता दें कि, ज्योति के साथ तो चीन ने चालबाजी की कोशिश की थी। चीनी एथलीट की गलती पर याराजी को परेशान किया गया था, लेकिन भारतीय एथलीट ने इसका विरोध किया और फिर बाद में चीनी अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि याराजी सही थीं। उनका ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर में बदल गया। वहीं नीरज चोपड़ को 6 प्रयास की जगह 7 बार थ्रो करवाया गया,

क्योंकि उस दौरान चीनी अधिकारियों के मुताबिक कोई तकनीकी समस्या के चलते उनका पहला थ्रो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ।

अंजू बॉबी जॉर्ज ने उठाए सवाल

इस पर भारतीय एथलीट्स नीरज चोपड़ा काफी नाराज दिखे और उन्होंने इस पर खुलकर बातचीत की। साथ ही इस मुद्दे पर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की उपाध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज, जो नीरज के मैच के दौरान मैदान पर ही मौजूद थीं, नाराज दिखीं और उन्होंने इस मुद्दे को बखूबी उठाया भी है।

साथ ही गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरी पहली थ्रो की दूरी क्यों नहीं नापी। मेरे बाद हुई थ्रो को दूरी आई, लेकिन मेरी नहीं। मेरे साथ ऐसा किसी भी प्रतियोगिता में कभी नहीं हुआ। मुझे बताया गया कि ये अच्छी थ्रो थी, शायद 87-88 मीटर तक गई थी। अगर पहली थ्रो अच्छी जाती है तो एथलीट पर से दबाव हट जाता है। ज्योति के साथ भी गड़बड़ हुई, जेना ने दूसरी थ्रो फेंकी लेकिन उसे फाउल दिया गया। बाद में फैसला बदला गया। हालांकि, मैं जेना के लिए बेहद खुश हूं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया।

दूसरी तरफ अंजू ने कहा कि चीनी अधिकारी जानबूझकर भारतीय एथलीट्स को निशाना बना रहे हैं। वे धोखेबाजी कर हमारे एथलीट्स को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने नीरज से पहली थ्रो नहीं नापे जाने का विरोध करने को कहा। चीन में जीतना काफी कठिन है, लेकिन हमारे एथलीट थ्रोअ, जंपर श्रेष्ठ हैं, इस लिए उन्हें परिशान किया जा रहा है।

हालांकि, आखिर में ज्योति, नीरज और किशोर ने सिल्वर और गोल्ड मेडल जीतकर चीनी अधिकारियों को मुहंतोड़ जवाब दिया।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले इंडिया को बड़ा झटका

बल्लेबाज शुभमन गिल को हुआ डेंगू

नई दिल्ली ,06 अक्टूबर 2023। क्रिकेट के महाकुंभ विश्व कप 2023 का आगाज हो लगा है। भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहले मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने जा रही है। यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम पर खेला जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाजी शुभमन गिल डेंगू की चपेट में आ गए हैं, ऐसे में गिल का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। गौर हो कि शुभमन गिल इस समय बेहद शानदार फार्म में चल रहे हैं। पहले एशिया कप और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में गिल ने शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में गिल का डेंगू की चपेट में आना भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका है। कयास लगााए जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच में गिल टीम का हिस्सा नहीं लेंगे।

अगर शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से बाहर होते हैं तो फिर भारतीय टीम में उनकी जगह ईशान किशन लेंगे। ईशान किशन मुख्य रूप से ओपनर हैं, लेकिन वो वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे हैं।

फिल्म लियो का ट्रेलर हुआ जारी

संजय दत्त से भिड़े थलापति विजय; खूंखार अवतार ने जीता दिल

पिछले काफी समय से फिल्म लियो सुर्खियों में बनी हुई है। यह फिल्म इसलिए खास है, क्योंकि साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय इससे जुड़े हैं, जो एक से बढ़कर एक फिल्में दर्शकों को दे चुके हैं।अब वह लियो लेकर आ रहे हैं, जो एक साथ कई भाषाओं में रिलीज होगी। संजय दत्त भी इस फिल्म से जुड़े हैं। अब नई खबर ये है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है।

फिल्म में एक्शन से लेकर ड्रामा, वो सबकुछ है, जिसकी उम्मीद विजय के प्रशंसक उनसे करते हैं।एक तरफ जहां उनका ताबड़तोड़ एक्शन ध्यान खींचता है, वहीं संजय के साथ उनका टकराव भी देखते ही बनता है।संजय की दमदार झलक देखने को मिली है, वहीं शेर की तरह दहाड़ते विजय का खौफनाक अवतार भी फिल्म की रिलीज को लेकर उत्सुकता बढ़ाता है।बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार है और अभिनेत्री तृष्णा कृष्णन संग विजय की जोड़ी भी जंच रही है।

इस फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है, जिनकी कैथी, विक्रम और मास्टर जैसी पिछली फिल्में हिट हुई हैं।अब वह विक्रम की सफलता के बाद लियो दर्शकों के बीच पेश करने वाले हैं। विजय और कनगराज इससे पहले मास्टर में साथ काम कर चुके हैं।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के केरल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 16 करोड़ रुपये में बिके हैं। यह केरल में किसी भी गैर-मलयालम फिल्म के लिए किया गया अब तक का सबसे बड़ा सौदा है।

बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक अनुराग कश्यप भी इस फिल्म में अभिनय करते नजर आएंगे। फिल्म में अनुराग के अलावा निर्देशक, मैसस्किन और गौतम मेनन भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं।अनुराग ने खुद लोकेश की किसी फिल्म का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की थी। वह लोकेश की फिल्मों से काफी प्रभावित थे।लियो मूल रूप से तमिल में बनी है, लेकिन इसे हिंदी समेत अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा।फिल्म 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी।

बॉलीवुड के कई सितारे साउथ की फिल्मों में दिखने वाले हैं। सैफ अली खान को जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा में देखा जाएगा। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी कल्कि 2898 एडी तो अर्जुन रामपाल अभिनता नंदमुरी बालकृष्णा की फिल्म भगवंत केसरी में दिखेंगे।

विजय ने बाल कलाकार के तौर पर भी कई फिल्मों में काम किया, जबकि बतौर लीड अभिनेता उनकी पहली फिल्म नालया थीरपू थी, जो 1992 में रिलीज हुई थी।उन्होंने इंटरनेशनल अचीवमेंट रिकॉग्निशन अवॉर्ड और साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड समेत कई पुरस्कार जीते हैं।विजय को आखिरी बार फिल्म वारिसु में देखा गया था, जो सुपर-डुपरहिट रही थी। वह मास्टर, मर्सल, बिगिल, सरकार और थुप्पक्की जैसी कई सफल फिल्मों से दर्शकों को अपना मुरीद बना चुके हैं।

रश्मि देसाई ने बिखेरे कातिलाना अदाओं के जलवे

टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई एक लंबा वक्त इंडस्ट्री में बिता चुकी हैं. इस दौरान उन्होंने घर-घर में अपनी एक खास जगह बना ली है. आज कोई रश्मि की अदाओं पर फिदा है, तो कोई उनकी अदाकारी का दीवाना है. ऐसे में एक्ट्रेस किसी न किसी कारण लगातार खबरों में बनी ही रहती हैं. फिलहाल तो रश्मि अपने नए फोटोशूट के कारण सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं.

लेटेस्ट फोटोज के लिए रश्मि देसाई ने व्हाइट-येलो चेक प्रिंट वाला ब्रॉडनेक क्रॉप कैरी किया है. इसे उन्होंने ग्रीन पैंट के साथ पेयरअप किया है. एक्ट्रेस ने अपने इस लुक को सटल बेस, न्यूड ग्लॉसी लिप्स और न्यूड स्मोकी आई मेकअप से कंप्लीट किया है.

रश्मि ने इस लुक के साथ अपने हाफ बालों का हाई बनाया हुआ है. वहीं, एक्सेसरीज के तौर पर उन्होंनें एक हाथ में ब्रेसलेट और गले में टू लेयर्ड चेन पहनी है.

रश्मि इस लुक में भी बहुत गॉर्जियस लग रही हैं. उन्होंने अपना स्टाइलिश अवतार कैमरे के सामने फ्लॉन्ट करते हुए एक से एक किलर पोज दिए हैं. अब फैंस के बीच उनका ये नया फोटोशूट भी काफी वायरल होने लगा है. यूजर्स ने उन्हें खूबसूरत और क्यूट बताते हुए कई कमेंट्स भी किए हैं.

दूसरी ओर रश्मि के वर्क फ्रंट की बात करें तो इस समय वह मिशन लैला टाइटल से बन रही हिन्दी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. इसके अलावा रश्मि के पास मॉम ताने ना समजे गुजराती और चंबे दी बूटी टाइटल से बनने वाली पंजाबी फिल्मों की तैयारी में भी व्यस्त चल रही हैं. रश्मि के चाहने वाले उन्हें फिर पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं.

वॉर 2 में पहली बार साथ आएगी सलमान,शाहरुख और ऋतिक की तिकड़ी

यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, इसलिए इसकी दूसरी किस्त को लेकर दर्शक बेहद उत्साहित हैं। अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों का उत्साह दोगुना कर देगी।दरअसल, निर्देशक अयान मुखर्जी ने सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को अपनी इस फिल्म में साथ लाने की बड़ी जिम्मेदारी उठाई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अयान इसी महीने वॉर 2 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। सेट पर इसका मुहूर्त भी हो चुका है।ऋतिक फिलहाल फिल्म फाइटर की शूटिंग के लिए इटली में हैं। वह जल्द ही वॉर 2 की शूटिंग शुरू करने के लिए भारत आएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीच जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म के लिए कियारा आडवाणी के नाम पर मोहर लग चुकी है।

सूत्र ने बताया कि वॉर 2 कई मायनों में दिलचस्प होने वाली है। सबसे बड़ी वजह यह है कि अयान इस फिल्म से पहली बार शाहरुख, सलमान और ऋतिक को पर्दे पर साथ ला रहे हैं यानी एक्शन का जबरदस्त डोज मिलने वाला है।फिल्म में वाईआरएफ यूनिवर्स के तीनों जासूसों पठान, टाइगर और कबीर को साथ देखना दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव होने वाला है।यह स्पाई यूनिवर्स की अयान के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म है।

अयान ने 2009 में 26 की उम्र में फिल्म वेकअप सिड से निर्देशन की शुरुआत की। हालांकि, इससे पहले वह शाहरुख की स्वदेश और कभी अलविदा ना कहना के सहायक निर्देशक रह चुके थे। ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र उन्हीं के निर्देशन में बनी।

बता दें कि वॉर 2 में एनटीआर विलेन बने हैं और खास बात यह है कि वह इसके जरिए बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। वॉर 2 में ऋतिक के साथ उनकी जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी।इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि आदित्य चोपड़ा अपने स्पाई यूनिवर्स की दूसरी फिल्म टाइगर 3 में एनटीआर का परिचय दर्शकों को कराने वाले हैं।फिल्म में सलमान उर्फ टाइगर, वॉर 2 के खलनायक यानी एनटीआर का परिचय कराते दिखेंगे।वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में ऋतिक के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे और इसमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। फिल्म में ऋतिक और टाइगर की जुगलबंदी कमाल की थी। इसमें ऋतिक एजेंट कबीर की भूमिका में थे।फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने आदित्य के साथ मिलकर इस फिल्म की कहानी भी लिखी थी।175 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 475 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।

CMYK

मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा पर हुआ त्वरित अमल

पत्रकार अब आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के लिए कर सकेंगे आवेदन

रायपुर,06 अक्टूबर 2023(ए)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा 'श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना' के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। योजना अंतर्गत 30 लाख तक के आवास ऋण के लिए 5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 के बाद से क्रय मकान पर प्रभावशील होगी। योजना से संबंधित नियम एवं आवेदन का प्रारूप जनसंपर्क विभाग की वेबसाईट डीपीआर सीजी. जी ओव्ही.आईएन से प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस पहल से प्रदेश के पत्रकार अब किफायती दर पर आवास का सपना पूरा कर सकेंगे।

योजना का लाभ केवल आवासीय ऋण पर दिया जाएगा तथा क्रय किया जाने वाला मकान छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होना चाहिए। ब्याज अनुदान अधिकतम 30 लाख रुपए के आवास ऋण की सीमा तक दिया जाएगा। संचार प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक ऑ इंडिया से अधिसूचित वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी बैंकों से लिए गए आवास ऋण पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। योजना का लाभ न्यूनतम 5 वर्ष से छत्तीसढ़ में निवास कर दैनिक समाचार तथा टी.वी. न्यूज चैनल्स में पंजीकृत समाचार एजेंसियों के सम्पादकीय शाखा में कार्य कर रहे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक संचार प्रतिनिधि तथा अधिमान्यता नियमों की अर्हतादायी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज पोर्टल्स के सम्पादक एवं स्वतंत्र पत्रकार ले सकेंगे।

संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लें तभी होगी पात्रता

संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लेने पर ही इस योजना की पात्रता होगी। योजना मात्र एक आवास ऋण में ही लागू होगी। किसी संचार प्रतिनिधि द्वारा पूर्व से अपने अथवा पत्नी के स्वामित्व का मकान योजना लागू होने के बाद अवयस्क/वयस्क संतान को अंतरित कर नया आवास लेने की दशा में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

पूर्व से स्वीकृत आवास ऋण पटाकर नये आवास ऋण प्राप्त करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। संचार प्रतिनिधियों द्वारा नियमित ऋण एवं ब्याज अदायगी करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा। डिफॉल्टर होने की स्थिति में योजना के लाभ की पात्रता स्वयमेव समाप्त हो जायेगी।

शपथ पत्र भी देना होगा

योजना में पात्रता के लिए स्वयं अथवा पत्नी, आश्रित पुत्र-पुत्री के नाम से कोई अन्य आवासीय भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा। शपथ पत्र के साथ संचार प्रतिनिधियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत बैंकों अथवा रजिस्ट्रीकृत वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण के प्रमाणित अभिलेख जनसम्पर्क संचालनालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

नियमित भुगतान कर बैंक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा

संचार प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए ऋण पर मासिक किश्त का नियमित भुगतान स्वयं करना होगा, बैंकों को ऋण के मूल एवं ब्याज के नियमित भुगतान करने संबंधी बैंक का प्रमाण-पत्र जनसम्पर्क संचालनालय में प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की गणना कर संबंधित पत्रकार के बैंक खातों में राशि दी जाएगी। योजना राशि की गणना - ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक की जाएगी किसी भी दशा में अनुदान राशि का भुगतान एकजाई नहीं किया जायेगा। आवास ऋण ब्याज अनुदान की गणना इस प्रकार होगी। इसमें वित्तीय वर्ष में बैंक में देय ब्याज को पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान से गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को बैंक ब्याज प्रतिशत दर से भाग दिया जाएगा। आवास ऋण 30 लाख रुपए से अधिक होने की दशा में ब्याज अनुदान की गणना दो चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में अधिकतम 30 लाख रुपए की राशि तक की ब्याज गणना की जाएगी। इसमें योजनान्तर्गत अधिकतम राशि(30 लाख रुपए) को वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ऋण पर देयक ब्याज राशि से गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को स्वीकृत आवास ऋण राशि से भाग दिया जाएगा। द्वितीय चरण में ब्याज अनुदान राशि की गणना की जाएगी। इसमें प्रथम चरण में गणना पश्चात प्राप्त ब्याज राशि को पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को बैंक ब्याज प्रतिशत दर से भाग दिया जाएगा।

योजना हेतु समिति करेगी अनुशंसा

प्रथम बार ब्याज अनुदान स्वीकृति के लिए संचालनालय में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विचार कर अनुशंसा करेगी। समिति में आयुक्त/ संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, अपर संचालक (पत्रकार कल्याण), अपर संचालक (समाचार), उप संचालक / संयुक्त संचालक (वित्त) शामिल होंगे।

योजना हेतु निर्णयात्मक शर्त/अधिकार

ब्याज अनुदान स्वीकृत करने के किसी भी प्रश्न पर तत्समय में प्रचलित अधिमान्यता नियमों में उल्लेखित संचार संस्थान एवं संचार प्रतिनिधि की अर्हतादायी शर्तों पर भी विचार किया जायेगा। ब्याज अनुदान स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त /संचालक, जनसम्पर्क को होगा।

पंचायत सचिवों के अवकाश व वेतन वृद्धि को लेकर आदेश जारी

रायपुर,06 अक्टूबर 2023(ए)। छत्तीसगढ़ में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं का स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, सेवानिवृति पर उपादान की पात्रता रहेगी। एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी। इसके अलावा महिला ग्राम पंचायत सचिव जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को 180 दिन के लिए मातृत्व अवकाश (गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जनम के 6 माह तक के लिए) स्वीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत सचिवों को भविष्य में इस आदेश के तहत किसी भी प्रकार के अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं होगी।

उपादान : 5 वर्ष से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को उनके सेवानिवृत्त होने पर अर्हतादायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण 6 माही समयावधि के लिए उनकी अंतिम उपलब्धियों के एक चौथाई के बबराबर, उपलब्धि के 16.5 गुना से अधिकतम के मध्याधीन रहते हुए उन्हें उपादान

मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

» **मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज शाम उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई।**

» **महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया**

रायपुर,06 अक्टूबर 2023(ए)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां उनके निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए ।छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ के वृक्ष बहुतायत में पाये जाते हैं। महुआ के फूल का पशु, पक्षी एवं मनुष्य सभी उपयोग करते है। महुए के बीज से तेल भी निकलता है। महुआ के फूल में औषधीय गुण भी मौजूद हैं तथा इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्त्रोत है। राज्य में महुआ की उपलब्धता तथा इसके उपयोग की बाहुलता एवं वन तथा वनक्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके विकास हेतु विशेष प्रयास किया जाए, जिससे महुआ के फूल, फल एवं बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण हो सके। इसके खाद्य एवं औषधीय उपयोग के साथ-साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके तथा बायोडीजल या एथनॉल के उत्पादन हेतु उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा पर मंत्रिपरिषद द्वारा त्वरित अनुमोदन ÷ मुख्यमंत्री जी द्वारा आज कांकेर के

गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारी जो एक जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए है उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से स्टेट पॉवर कंपनीज के करीब 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

➡छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया।

➡ग्राम पंचायत भोरिंग, जिला-महासमुंद को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

➡नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी को नगर पालिका उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

➡नगर पंचायत नवागढ़, जिला-बेमेतरा को नगर पालिका परिषद बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

➡स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी संबंधी कार्यवाही को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया गया।

➡श्री कल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संस्कार अध्ययन शाला, चिकित्सालय एवं गौशाला निर्माण हेतु आबंटित भूमि के प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक, पर्यावरण उपकर तथा अधोसंरचना उपकर में रियायत देने का निर्णय लिया गया।

➡खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मार्कफेड में प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकृत संयुक्त संचालक के 01 पद को अपर संचालक के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया।

➡लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर में अपर संचालक के दो पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।

आचार संहिता लगने से पहले 49 डीएसपी का ट्रांसफर

रायपुर,06 अक्टूबर 2023(ए)। छत्तीसगढ़ पुलिस के 49 डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है। कई अफसरों को दूसरे जिलों में जिम्मेदारी मिली है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने से पहले 49 डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है।रायपुर के विधानसभा इलाके के सीएसपी उड्डयन बेहार को डीएसपी मुख्यालय बिलासपुर भेजा गया है। वही डीएसपी एसीबी सुरेश ध्रुव को सीएसपी विधानसभा बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता समिति गठित

श्रीवास्तव होंगे अध्यक्ष

रायपुर,06 अक्टूबर 2023(ए)। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत 'छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति' का गठन किया गया है। समिति गठन के संबंध में मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर स्थित जनसंपर्क विभाग से आज जारी आदेश के तहत समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) होंगे।जारी आदेश के तहत समिति

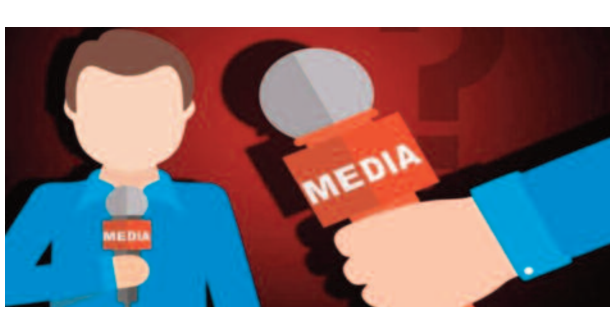

के सदस्यों में पुष्पा रोकड़े, संवाददाता, प्रखर समाचार, बीजापुर, दिवाकर मुक्तिबोध, वरिष्ठ पत्रकार, रायपुर, नथमल शर्मा, प्रधान संपादक, ईवनिंग टाईम्स, बिलासपुर तथा संचालक लोक अभियोजन द्वारा नामित संघ के संचालक स्तर का अधिकारी शामिल है। इसके अलावा आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क द्वारा नामित अपर संचालक स्तर के अधिकारी समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

नक्सलियों का प्लान किया फेल

सुकमा,06 अक्टूबर 2023(ए)। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर जवानों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया हैं। बता दें कि सुरक्षा कर्मी के जवानों ने बरामद दो आईईडी बमों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि, जिला सुरक्षा बल के कैंप बड़े सेट्टी एवं चिंतलनार से डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और जिला बल के जवान संयुक्त रूप से नक्सल अभियान पर निकले थे।

इस दौरान बगड़ेगुड़ा और इत्तापारा के समीप नक्सलियों द्वारा जवानों को हानि पहुंचाने की नियत से लगाए गए दो आईईडी बम बरामद किए गए। इसके बाद जवानों ने सुरक्षा पैमानों का पालन करते हुए पूर्ण सतर्कता के साथ मौके पर ही आईईडी विस्फोट कर नष्ट कर दिया है।

शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर समेत चार की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

बिलासपुर,06 अक्टूबर 2023(ए)। शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए अनवर ढेबर समेत चार लोगों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन समेत अनवर ढेबर की की अंतरिम बेल भी खारिज कर दी है. बता दें कि ईडी ने अनवर ढेबर को 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला का दोषी बताया है. गिरफ्तारी के बाद ढेबर को हाईकोर्ट ने स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर अन्तरिम जमानत पर छोड़ा है, लेकिन रेगुलर याचिका खारिज होने के बाद अनवर ढेबर की समस्या बढ़ गई है.

ईडी ने छापामार कार्रवाई के बाद आरोप लगाया कि प्रदेश में 2 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है. पूछताछ के बाद बाद ईडी ने रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया. स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर अनवर के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया. कोर्ट ने स्वास्थ्य के मद्देनजर अनवर ढेबर को अन्तरिम जमानत पर मुहर लगाया था. मामले में पिछले दिनों ढेबर की तरफ से हाईकोर्ट में रेगुलर याचिका के लिए आवेदन दाखिल किया गया. आज सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति गौतम भादुडी की कोर्ट ने अनवर ढेबर की रेगुलर याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है.

बिलासपुर-दिल्ली के बीच शुरू हो रहे हवाई यात्रा के लिए

चकरभाठा एयरपोर्ट में हुआ ट्रायल

बिलासपुर,06 अक्टूबर 2023(ए)। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर से दिल्ली के बीच हवाई यात्रा शुरू करने की मांग क्षेत्र की जनता द्वारा लगातार की जा रही थी। जनता की मांगों के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्र लिखने के बाद बिलासपुर एयरपोर्ट में दिल्ली की फ्लाइट के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मिल गई है। जिसके बाद आज चकरभाटा एयरपोर्ट पर ट्रायल भी किया गया। एलाइंस एयर ने इसकी सुविधा दी। संभवतः विंटर सीजन में बिलासपुर से दिल्ली तक के लिए नई फ्लाइट मिल सकती है। एलाइंस एयर की फ्लाइट प्रयागराज से आकर सीधे दिल्ली जाएगी जो कि शनिवार और रविवार को उड़ेगी।

बता दें कि बीते मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा था। पत्र में सीएम भूपेश ने बिलासपुर एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों में विमान सेवा आरंभ करने और रायपुर-जगदलपुर-हैदराबाद एयर रूट पर विमान सेवा के लिए अलायंस एयर से अनुबंध की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था।पत्र में उन्होंने बंद किये गये बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर और बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर विमान सेवा फिर से शुरू किये जाने का अनुरोध भी किया था। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा था कि जगदलपुर विमान सेवा के चलते बस्तर को देश के पर्यटन नक्शे में आने का मौका मिला है और बस्तर की संस्कृति राष्ट्रीय पटल पर उभरी है. बिलासपुर से भी नागरिक सुविधाओं को देखते हुए प्रमुख शहरों से विमान सेवाएं आरंभ किये जाने की जरूरत है।

मलेशियन नोट की लालच में मिली रद्दी

रायपुर/भिलाई,06 अक्टूबर 2023(ए)। एक व्यापारी को मलेशियन नोट की जगह रद्दी थमाने का मामला सामने आया है। साढ़े तीन लाख रुपए की ठगी करने वाले तीन शातिरों के खिलाफ सुपेला पुलिस ने धोखाधड़ी की धरा के तहत केस दर्ज किया। शातिरों ने पहले व्यापारी को 50 मलेशिया करेंसी दिया, और कहा की उनके पास मलेशिया की काफी नोट है। नोटों को बदलकर कमीशन कमाने के लालच में व्यापारी उनके बातों में फंस गया और साढ़े तीन लाख रुपये गवां बैठा।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता की भिलाई-3 में कपड़े की दुकान है। 23 सितंबर को तीनों आरोपित शिकायतकर्ता की दुकान पर पहुंचे थे। वहां पर

आरोपितों ने दुकान से अंडरवियर खरीदा और उसका भुगतान किया।

आरोपितों के जाने के बाद शिकायतकर्ता ने अपने एक परिचित को 50 मलेशियन नोट दिखाया। उसके दोस्त ने नोट को देखकर बोला कि नोट असली है,और भारत में इसकी कीमत 800 रुपये के आसपास है। उस दोस्त ने कहा कि इन नोट को बदलकर वे अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। इसके बाद पीड़ित ने आरोपितों से संपर्क किया। आरोपितों ने बताया कि उनके पास 50 रिंग्गित के 1660 नोट हैं। आरोपितों ने नोटों की गड्डी दिखाई। उसमें से उन्होंने आठ नोट निकालकर भी दिखाए। विश्वास होने पर उनके बीच उन नोट का सौदा साढ़े तीन लाख रुपये में तय हुआ। 27 जून को वे लोग नोट लेने के लिए गदा चौक पहुंचे। जहां पर आरोपित एक झोले में नोट लेकर पहुंचे थे।

पीड़ित व उसके दोस्त ने उन्हें साढ़े तीन लाख रुपये देकर वो झोला ले लिया। रुपये लेकर आरोपित वहां से चले गए। आरोपितों के जाने के बाद उन्होंने झोले से नोट निकालकर देखा तो उसमें रद्दी भरा हुआ था। इसके बाद पीड़ित ने सुपेला थाना में घटना की शिकायत दर्ज कराइ। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत प्राथमिकी कर उनकी तलाश शुरू की है।

फेसबुक में एसपी बन गया ठग

आईपीएस का नाम इस्तेमाल कर मांग रहा पैसे

बिलासपुर,06 अक्टूबर 2023(ए)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ठगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि, ठगों ने बिलासपुर के एसपी संतोष कुमार सिंह के नाम पर फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। इसको लेकर एसपी ने जानकारी शेयर की है और लोगों को इनसे बचने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार, बिलासपुर के एसपी आईपीएस संतोष कुमार सिंह के नाम पर ठगों ने सोशल मिडिया पर अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे की मांग कर रहे हैं। ठग अलग-अलग बहाने बनाकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं. मामले की जानकारी मिलते ही एसपी ने स्क्रीनशॉट शेयर कर लोगों को इनसे बचने की सलाह दी है। साथ ही प्रोफाइल को रिपोर्ट करने और किसी की भी प्रकार का लेनदेन ना करने की हिदायत भी दी है।

13 साल से फरार हत्या के आरोपी को क्राइम ब्रांच रायपुर ने दबोचा

रायपुर,06 अक्टूबर 2023(ए)। 13 साल से फरार हत्ते या के आरोपी को क्राइम ब्रांच रायपुर ने दबोचा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हत्या करने के बाद वह रायपुर में अलग-अलग स्थान में रह रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी मनोज सिंह टिकरापारा इलाके में रहकर काम कर रहा था।

क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश की टीम से संपर्क किया है। आरोपी के खिलाफ बलवा, हत्या का प्रयास और हत्या सहित गंभीर आरोप है। रायपुर क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपित रायपुर में रहा है। आरोपी पर हत्या, बलवा, हत्या का प्रयास, बलवा सहित गंभीर आरोपों के तहत केस दर्ज है।

इसके बाद से पुलिस ने मुखबिर लगाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपित यहां अपने परिवार के साथ टिकरापारा क्षेत्र में रह रहा था। वह ट्रांसपोर्ट में काम करता था। पुलिस के मुताबिक मध्यप्रदेश के बरहवाटोला बरगवो में वर्ष 2010 में एक युवक की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी। इसमें अन्य आरोपियों के साथ मनोज सिंह भी शामिल था। मनोज वहां से फरार हो गया। बाकी आरोपी पकड़े गए। आरोपित मनोज अपने रिश्तेदारों के पास रायपुर आ गया।रायपुर में अपने रिश्तेदार के ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने लगा। पिछले 13 साल से उसी के यहां रह रहा था। कुछ दिन पहले रायपुर पुलिस को मनोज के बारे में जानकारी मिली।इसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) की टीम को लगाया गया था। टीम ने जानकारी जुटाने के बाद मनोज को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। देर रात तक पुलिस उससे पूछताछ करती रही। हालांकि टीम ने पूरे मामले की जानकारी मध्यप्रदेश पुलिस को दे दी है। रायपुर एसीसीयू टीआई गिरीश तिवारी ने कहा, मामले की सूचना मिली थी। इसके बाद मनोज सिंह को पकड़ा गया है। पूरा मामला एमपी का है। वहां की पुलिस को जानकारी दी गई है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No. CHHHIN/2004/15050,मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)